कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

lnL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

मेरठ (उ.प्र.) में आयोजित महासंग्राम रैली के दौरान बसपा सरकार के 100 घोटाले पर केन्द्रित पुस्तिका का लोकार्पण

महासंग्राम रैली

मेरठ (उ.प्र.)..... 7
काशी (उ.प्र.)..... 9
रायपुर (छत्तीसगढ़)..... 13
चित्रकूट (म.प्र.)..... 24

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार पर रिपोर्ट

सुशासन का मुद्दा उठा रही है भाजपा..... 10

साक्षात्कार

श्रीमती सुषमा स्वराज..... 14
प्रो. प्रेम कुमार धूमल..... 19

विशेष

नितिन गडकरी का एक अलग चेहरा..... 16

लेख

विकीलीक्स केबल्स सच्चाई हैं, असांजे की पुष्टि
&ykyÑ".k vkMok.kh..... 22
चीन की उल्लेखनीय प्रगति, परन्तु अतीत का अनादर नहीं
&jfo'kdj çlkn..... 26

अन्य

डॉ. अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम..... 6
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न..... 25

वैचारिकी

कांग्रेस और जनतंत्र
&i- nhun;ky mik/;k;..... 28

संपादक के नाम पत्र...

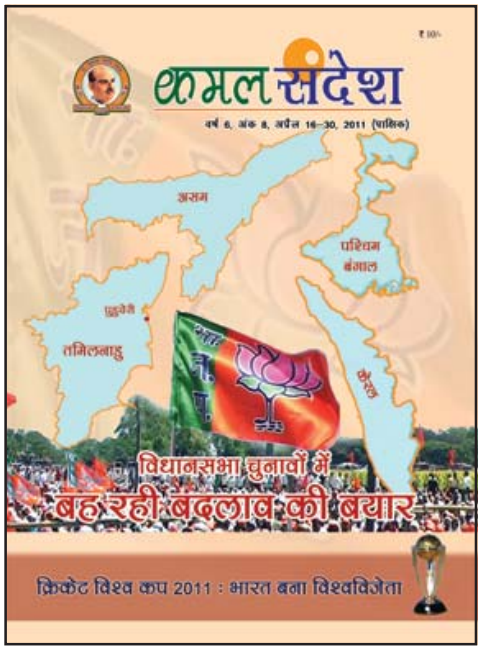

dkx:l dk gkFk Hk"Vkpkfj;k d: lkFk

भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं लेकिन काला धन इसका सबसे भयावह चेहरा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी' के अनुसार भारत के लोगों का लगभग 20 लाख 85 हजार करोड़ रूपए विदेशी बैंकों में जमा है। देश में काले धन की समानांतर व्यवस्था चल रही है। चूंकि इस धन पर टैक्स प्राप्त नहीं होता है इसलिए सरकार अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी करती है, जिसके चलते नागरिकों पर महंगाई समेत तमाम तरह के बोझ पड़ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विदेशों में जमा काले धन के मामले को जोरशोर से उठाया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन करते हुए प्रचार अभियान में वादा किया था कि सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर वे इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेंगे लेकिन वह अपने वायदों से दूर भाग रहे हैं। काले धन पर यूपीए सरकार के ढुलमुल रवैये से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है।

&lkjHk dekj
मधुबनी, बिहार।

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें..

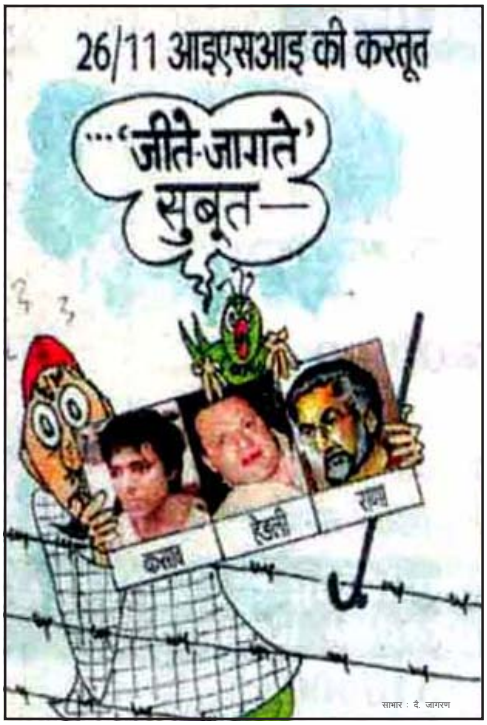

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

राजनैतिक दल जनाकांक्षा को समझें

सम्पादकीय

jk जनीति में 'संघर्ष' शब्द से दूरी बनाकर अगर कोई राजनेता सुविधा के आगे नतमस्तक होते हुए अपनी राजैनतिक हैसियत को समाज और राष्ट्र में कायम करना चाहेगा तो शायद वह गलतफहमी का शिकार होगा। भारत ने समर्पण और संघर्ष, परिश्रम और पराक्रम, नैतिकता और ईमानदारी को कभी मरने नहीं दिया। भारत ने उन नेताओं को सदैव सराहा, जिन्होंने ईमानदारी के पन्ने पर अपने राजनैतिक जीवन का इतिहास लिखा।

हमने लंगोटी पहनने वाले महात्मा गांधी को बापू कहा और राष्ट्रपिता की उपाधि दी तो उसके पीछे भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन ही नहीं बल्कि एक जीवंत संघर्ष, वह भी भारत की अस्मिता का ऐतिहासिक और गरिमामयी पन्नों से जुड़ा है। वर्तमान राजनीतिज्ञों को समझना होगा कि भारत की जनता लाखों–करोड़ों आंखों से उन्हें देखती है। संचार और मीडिया की बदलती प्रकृति और उसकी तेज गति के कारण अब कोई बच नहीं सकता। अतः सबको सतर्क ही नहीं बल्कि अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी होगी। 'भारतीय राजनीति' पर यदि हम प्रभाव डालना चाहते हैं या वर्तमान राजैनतिक दशा–दिशा को बदलना चाहते हैं तो हमें 'भ्रष्टाचार मुक्त और नैतिकता युक्त' जीवन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। अभी हो यह रहा है कि देश भ्रष्टाचारमुक्त होना चाहिए, ये बातें तो सभी कह रहे हैं, पर यह बात भारतीय जीवन शैली में अमल कैसे हो, इसकी दिशा में कोई सार्थक और समर्थ पहल, जो सदैव जनजागरण करता रहे, प्रारम्भ नहीं हो रहा।

राजनेताओं को भी स्वयं यह सोचना होगा, कि आज समाज में उनकी साख क्यों कम हो रही है और उनके प्रति जनता में अनास्था क्यों पैदा हो रही है? भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए वर्तमान में सबसे चिंतनीय विषय यही है। साख की समाप्ति और अनास्था का जन्म लेना लोकतंत्र में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है।

भारतीय दार्शनिक, मनीषियों और चिंतकों ने वेद पुराणों में सदैव कहा है कि जिस राजा ने अपने को जन का यानि प्रजा का सेवक माना वे सदैव लोकप्रिय रहे। वहीं जिस राजा ने अपनी प्रजा का अपमान किया, वे कूड़ेदान में फेंक दिए गए। आज के राजनीतिज्ञों और जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि वे लोकसेवक हैं। सेवा उनकी प्राथमिकता है। 'समर्पण' उनका संस्कार है। नैतिकता उनकी नीतिगत आवश्यकता है। स्वयं की प्रगति से पूर्व समाज की प्रगति उनका लक्ष्य है। राजनीतिज्ञों के बारे में जब आमजन में चर्चा होती है तो वह आमजन चाहता है कि उसका नेता सादगी से भरा हो। उसका जीवन संस्कार से जुड़ा हो। विनम्रता उसमें कूट–कूट कर भरी हो। सामाजिकता का बोध हो। वह सहज उपलब्ध रहे। वह उसके दुख–सुख का साथी हो। उसका नेता भ्रष्ट न हो। वह ऐसा कार्य करे कि उसकी जनता उस पर गौरव महसूस करे। इससे अधिक अपेक्षा आमजन की नेता से नहीं होती है। काश! ऐसा होता।

आज राजनैतिक दल पार्ट टाईम के धरने और पूड़ी–सब्जी युक्त 'चार पहिये' से जेल के बाहरी मैदान पर पहुंचकर अपने को शहीद कहलवाना चाहता है। यह कैसे सम्भव होगा? स्थिति इतनी भयावह है कि लोग भाषण से देश को ठीक करना चाहते हैं जबकि देश को आज नैतिक आचरण वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। यह सब बातें आजकल जन के मन में चल रही बातें हैं। जनता जो वर्तमान में सवाल करती है कि कितने दिन हो गए एक नेता को जिसने यह प्रयास किया हो कि नहीं मैं भारत का दर्शन एक सांस में करूंगा। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ अध्यक्ष के रूप में एक नहीं अनेक बार भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भारत को आकाश से नहीं जमीन पर जमीनी प्रवास से देखने की कोशिश की। अतः कम समय जीवित रहने के बाद भी वे आज तक जीवित हैं और आज उनके चित्र के समक्ष दीप जलाकर ही हरेक कार्यक्रम प्रारम्भ होता है।

अतः आज की महती आवश्यकता है कि भारतीय राजनैतिक दल और राजनीति को इंडिया शैली की राजनीति न करते हुए भारतीय शैली की राजनीति करें।

देश को भारत में भारतीय शैली से चलने वाली राजनीति की आवश्यकता है यह सपना अब 'कोमा' में जा चुकी कांग्रेस से संभव नहीं। इसका मूल कारण है कि कांग्रेस अब पार्टी के बजाए एक परिवार की बंधक हो गई और वहीं यह भी लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक नौकरशाह के मूल स्वभाव से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि जनता एक नए विकल्प की ओर बढ़े। इस नए विकल्प में आम जनता भारत को देखना चाहती है न कि इंडिया को। आम जनता की इस आकांक्षा को वर्तमान राजनैतिक दलों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो पूरी कर सकती है। अतः भाजपा को तय करना होगा कि वह आम जनता की आकांक्षा पर कैसे खरा उतरे? ■

डॉ. अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम

सामाजिक-आर्थिक विषमता से मुक्त बने समाज : नितिन गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सामाजिक–आर्थिक विषमता से मुक्त समाज बनाना होगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर दलितों का दुख–दर्द मिटाने के लिए मसीहा बनकर आए थे।

गत 13 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में डॉ. अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य विषमता मुक्त समाज बनाने का है। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा भय, भूख, आतंकमुक्त, सामाजिक न्याय युक्त समाज की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि हम पशु–पक्षियों से तो प्यार करते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि 21वीं सदी में भी समाज मानव और मानव में भेद करता है। जब यह भेद रहेगा भारत का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे चाल, चरित्र और चिंतन में एका होनी चाहिए। इस अवसर में दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉ सम्बित पात्रा ने पावर–प्रेजेंटेशन के माध्यम से डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा ने अनुसूचित जाति के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की।

बाबा साहेब के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज दलित समाज को मान–सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है।

इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री श्री प्रवेश वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम, मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री कैलाश सांकला उपस्थित थे।■

भाजपा विकास की राजनीति में विश्वास करती है : नितिन गडकरी

fodkl vkuan dh fjiksVZ

Hkkरतीय जनता पार्टी ने 9 अप्रैल 2011 को ऐतिहासिक नगर मेरठ से अपने महासंग्राम रैली की शुरूआत की। इस रैली में मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। सभी तरह से यह रैली बहुत ही सफल रही। भारी संख्या में लोग अपने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता को सुनने के लिए आये। मेरठ का रामलीला मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था।

रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि इस राज्य में मेरी पहली रैली है। कहा जाता है और मेरा भी यह विश्वास है कि मेरठ की धरती से जो काम शुरू होता है वह अपने परिणाम तक पहुंचता है।

आगे श्री गडकरी ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है 10 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या की प्रतिव्यक्ति आय केवल 20 रूपये प्रतिदिन है जबकि महंगाई आसमान छू रही है। प्रत्येक साल 58 करोड रुपये का अनाज सड़ जाता है। अनाज के भण्डारन के लिए देश में कोई सुविधा नहीं है। भण्डारन की उचित सुविधा कराने में सरकार पूरी तरह से असफल है। ग्रामीण भारत ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। जैसा कि हम जानते है कि बिना ऊर्जा का विकास नहीं हो सकता। उतर प्रदेश में आलू सड़कों पर फेंक दिया जाता है क्योंकि भण्डारन की कोई सुविधा नहीं है। जब मैं लखनऊ गया तो मैंने देखा मुख्यमंत्री मायावती अपनी मूर्तियां बनवाने में व्यस्त हैं। यदि उन मूर्तियों पर किए गए खर्च का एक चौथाई भी कोल्ड स्टोरेज बनवाने मे खर्च करती तो किसानों को अपनी पैदावार को सड़क पर नही फेंकना पडता।

श्री गडकरी ने कहा कि मुख्यतः विकास के दो क्षेत्र हैं– कृषि और उद्योग। उद्योगों के विकास के लिए पानी, बिजली आदि की आवश्कता होती है। कृषि की उत्पादकता को बढाने के लिए अच्छा बीज, उर्वरक, इत्यादि की जरूरत होती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि बसपा शासित इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कृषि विकास दर 3 प्रतिशत है। और भाजपा शासित राज्य गुजरात की विकास दर 14 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह विकास दर हासिल क्यों नहीं कर पाया ?

आगे श्री गडकरी ने कहा कि जाति–मजहब पर आधारित राजनीति से विकास नहीं हो सकता। भाजपा केवल विकास की राजनीति पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनना है कि वे विकास की राजनीति चाहते हैं या फिर जाति, धर्म पर आधारित राजनीति चाहते हैं।

श्री गडकरी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्री हत्या

और बलात्कार के आरोप में त्यागपत्र दे रहे है और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस तरह की परिस्थितियों से राज्य का विकास कैसे हो सकता है? श्री गडकरी ने आरोप लगाया कि नोएडा में सरकार उद्योगपतियों को औने–पौने दामों में जमीन बेच रही है। राज्य भ्रष्टाचार में व्याप्त है। उन्होंने घोषणा की कि यदि भाजपा सत्ता में आएगी तो उत्तर प्रदेश का चहरा बदलेगा और किसानों को न्याय दिलायेगी। श्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण के अंत में प्रसिद्ध कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां कही।

हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

इससे पूर्व रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और भारत संकट से गुजर रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बचा लो !बचा लो उत्तर प्रदेश और भारत को। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आलोचना करती हैं और केन्द्र में कांग्रेस का समर्थन करती हैं। इसलिए आसमान छूती महंगाई के लिए जितना अधिक कांग्रेस जिम्मेवार है उतना ही अधिक मायावती। आगे उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य आसमान छू रहा है, इसका कारण भ्रष्टाचार घोटाला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में मात्र अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महंगाई को नियंत्रित किया था। जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है महंगाई और भ्रष्टाचार लाती है। श्री सिंह ने चेतावनी दी कि जनता का विश्वास राजनीति और राजनेता में कम हो रहे हैं। इसका कारण देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

काले धन के मुद्दे पर बोलते हुए श्री राजनाथ ने कहा कि बेईमान राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अधिकारी अवैध तरीके से कमाये हुए काले धन को स्वीज बैंक में भारी मात्रा में जमा कर रखा है। यदि अमरीका अपने काले धन को स्विस बैंक से अपने देश ला सकता है तो भारत क्यों नहीं ?एक रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख करोड़ भारतीयों का कालेधन स्विस बैंक मे जमा है। यदि उसे भारत लाया जाता है तो प्रतिवर्ष घाटे का बजट पारित नही होगा।

उन्होंने कहा कि जब तक गांव और किसान सुखी नही होंगे तब तक भारत सुखी नही हो सकता क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। इसलिए किसान सुखी रहेंगे तो देश के व्यापारी और लोकसेवक भी सुखी रहेंगे। कुल जीडीपी का 14 प्रतिशत किसानों द्वारा योगदान दिया जाता है। लेकिन उसका 2 प्रतिशत ही किसानों पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्यों में उर्वरक और बिजली किसानों को मुहैया नहीं कराया गया। आम लोगों का क्या कहना सरकारी अधिकारियों की राजधानी में दिन–दहाडे हत्या कर दी जाती है। श्री सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का भाग्य आप लोगों के हाथ में है आप लोगों को ही निर्णय लेना है।

श्री सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आएगी तो अनाज का समर्थन मूल्य 1120 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती करूणा शुक्ला ने लोगों से मायावती सरकार को उखाड़ फैंकने का आह्वान किया।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्रा ने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति के लिए जानी जाती है जो यात्रा यहां से शुरू की गई है वह जरूर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लायेगी। उत्तर प्रदेश में कुव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में दो चिकित्सा पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई। यदि सुश्री मायावती में थोडी–सी भी नैतिकता बची होती तो अपने पद से त्यागपत्र दे देती।

उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मायावती द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त करेगी।

उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि मायावती का एक ही मकसद है सरकारी योजनाओं से अधिक से अधिक अवैध पैसा बनाना। सुश्री मायावती ने नोएडा में भूखण्ड़ आवंटन में हुए भ्रष्टाचार से कमायें है। उन्होंने आरोप लगाया कि बलात्कारियों के लड़कों को मायावती विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण कर रही हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविंद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह महासंग्राम रैली मायावती के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी भाजपा सत्ता में है वहां सुशासन और विकास कायम है। भाजपा शासित प्रदेश राज्य विकास और सुशासन के लिए पुरस्कृत किये जा रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार ने कहा कि मुझे आशा है कि राज्य में परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन भाजपा सरकार के रूप में होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती गरीबों के कल्याण की जगह अपनी मूर्तियां लगवाने में व्यस्त हैं। मायावती 3 करोड़ 49

शेष पृष्ठ 13 पर...

भ्रष्टाचार से मुक्त विकास की राजनीति पर चलें : गडकरी

जम, रोजगार और राष्ट्र के साथ विकास की थीम पर भाजपा ने काशी से केंद्र और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ महासंग्राम का शंखनाद किया। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। महासंग्राम रैली की खास बात रही। हर किसी ने किसानों और गांवों की बेहतरी को ही देश की तरक्की का माडल बताया। बेनियाबाग मैदान भगवा रंग में रंगा था। यहां पूर्वांचल के १३ जिलों से उमड़ी भारी भीड़ को देख पार्टी नेता उत्साहित थे। आत्मविश्वास से भरे नेताओं ने इसे ऐतिहासिक रैली बताया।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि काशी में ऐसी रैली पहले नहीं देखी तो वरिष्ठ नेता डा. मुरली मनोहर जोशी ने इसे महाकुंभ की संज्ञा दी। खास बात यह रही कि एक जत्था रैलीस्थल पर पहुंचता तो दूसरा रैलीस्थल से रैली की समाप्ति तक निकलता रहा। पूर्वांचल में पहली बार किसी पार्टी कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने 30 मिनट के संबोधन में कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में राजग दिल्ली पर कब्जा करेगा। कांग्रेस, सपा और बसपा पर जोरदार हमले किए। कहा कि बसपा–सपा दोनों ही कांग्रेस के साझीदार हैं। यूपी में तीनों पार्टियां आपस में कुश्ती लड़ती दिखती हैं, लेकिन दिल्ली में दोस्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यहां केवल जाति की राजनीति हो रही है। ऐसे लोगों का विकास से कोई नाता रिश्ता नहीं होता। यूपी की जनता भूखी है, कंगाल है, करोड़ों बेरोजगार हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, यहां तो गुंडाराज है। इसीलिए यूपी को विकास की ओर ले जाना है। रैली से निकलने के क्रम में पत्रकारों से कहा कि पांच राज्यों में हो रहे चुनाव में असम में पार्टी की सरकार बनेगी।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भी केंद्र तथा प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए देश तथा प्रदेश को बचाने का लोगों का आह्वान किया। कहा कि कांग्रेस जब कभी सत्ता में आती है तो महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है। आर्थिक कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए केंद्र को समर्थन देने वाली सपा तथा बसपा भी समान रूप से भागीदार है। उन्होंने सुझाव दिया कि महंगाई को खत्म करना है तो उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों को बढ़ाना होगा। गांव तथा किसान को प्राथमिकता देनी होगी। किसान ही सबसे बड़ा ग्राहक है। इसलिए गांव तथा किसान दोनों को प्राथमिकता देनी होगी। डॉ. मुरली मनोहर जोशी के निशाने पर रही केंद्र सरकार और उसमें भी प्रधानमंत्री। कहा कमजोर प्रधानमंत्री के चलते भ्रष्टाचार बढ़ा है। देश में तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों में ही भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही ने उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरने का आह्वान किया। रैली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री विनय कटियार, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, विधानमंडल दल के नेता श्री ओमप्रकाश सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन प्रदेश महामंत्री डा. महेंद्र नाथ पांडेय ने किया। अध्यक्षता काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह चौहान ने की। ■

सुशासन का मुद्दा उठा रही है भाजपा

&lsoknnkrk }kjk

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव 6 चरणों में होने है। 18 अप्रैल को पहले चरण, 23 अप्रैल को दूसरे चरण, 27 अप्रैल को तीसरे चरण, 3 मई को चौथे चरण, 7 मई को पांचवे चरण और 10 मई को छठे चरण के चुनाव होने हैं। अब तक दो चरण के मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए हैं। पहले चरण में 74.27 प्रतिशत और दूसरे चरण में 84 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। हम यहां चुनाव प्रचार का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं :

सुशासन चाहिये तो भाजपा को वोट दें : लालकृष्ण आडवाणी

भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 15 अप्रैल को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता सुशासन चाहती है तो उसे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करना चाहिये। पूर्व उप प्रधानमंत्री ने जलपाईगुडी जिले स्थित इस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''भाजपा ऐसी एकमात्र पार्टी है जो अगर सत्ता में आयी राज्य में सुशासन का वादा कर सकती है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि वाम मोर्चे की सरकार ने अपने 34 वर्ष के शासन में कुछ नहीं किया। सडकों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पेयजल और अन्य सुविधाओं की राज्य में खराब स्थिति है।

श्री आडवाणी ने कहा कि केंद्र की संप्रग सरकार 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श आवासीय सोसायटी जैसे घोटाले कर रही है। संप्रग के शासनकाल में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है लेकिन सरकार महंगाई कम करने के लिये कोई भी कदम नहीं उठा पायी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ भाजपा ही सुशासन दे सकती है।

21 अप्रैल को नादिया जिले के नकाशीपाड़ा में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित सभा श्री लालकृष्ण आडवाणी ने पश्चिम बंगाल और गुजरात की तुलना करते हुए कहा कि जहां पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के 34 साल के शासन में विकास नहीं कर सका, वहीं गुजरात कम समय में ही आगे बढ़ गया है। श्री आडवाणी ने कहा, गुजरात आज सबसे अग्रिम राज्यों में है, वहीं मार्क्सवादी शासन के तहत पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार के शासनकाल में काफ़ी विकास हुआ था।

श्री आडवाणी ने मतदाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल में 1986 में कंप्यूटरीकरण का विरोध करने में वाम मोर्चा सरकार की भूमिका थी इसलिए इस थकी हुई सरकार को छुट्टी दे देनी चाहिए।

३४ वर्षों के शासन के बाद भी बंगाल की हालत दयनीय : राजनाथ सिंह

माथाभांगा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी सुशील बर्मन के समर्थन में पाड़ाडूबी में 15 अप्रैल को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने बांग्ला में चंद अलफाज में कहा : आमी बांग्ला बोलते पारी ना, थोड़ा थोड़ा बुझते पारी। ताई आमी हिन्दी ते बोलबो। भाजपा नेता ने कहा कि 34 वर्ष के शासन में वाममोर्चा सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। लेकिन यदि आप देखें तो भाजपा शासित राज्यों के विकास और पश्चिम बंगाल के विकास में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। उन्होंने कहा कि आप सब हमें वोट दें तो हम आपको

सुशासन देंगे।

आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्य इस सुशासन के नमूने हैं। केंद्र सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से बुरी तरह घिर गई है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार गरीबों को एक रुपए किलो की दर से मासिक 35 किलो चावल दिया जा रहा है। आप को भी मिल रहा है क्या? उन्होंने श्रोताओं से सवाल किया। भाजपा के शासन काल में ऐसी महंगाई नहीं थी। सड़क, बिजली एवं दूरसंचार के क्षेत्रों में हर तरफ विकास हो रहा था। पश्चिम बंगाल में फिलहाल केवल चार कारखाने चल रहे हैं। केरल में भी वाममोर्चा सरकार इस बार जाने वाली है। इस बार केंद्र में सत्ता में आने पर आप देखेंगे कि हम देश को कैसा विकास व सुशासन देते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत से लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि परिवर्तन विकास के लिए होना चाहिए। केवल सत्ता परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा।

भाजपा ही लाएगी असली परिवर्तन : अरूण जेटली

वाममोर्चा और तृकां–कांग्रेस जोट दोनों को निशाना बनाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष श्री अरूण जेटली ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है। लेकिन यह परिवर्तन वास्तव में भाजपा ही ला सकती है। श्री जेटली 15 अप्रैल को नागराकाटा में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश लाकड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। ज्ञात हो कि राजेश लाकड़ा को भाजपा के अलावा गोजमुमो व पीपीपी का भी समर्थन प्राप्त है।

स्थानीय योरोपियन क्लब मैदान में हुई जनसभा में श्री जेटली ने कहा कि डुवार्स में पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सबकुछ है। लेकिन इनका उपयोग करने के लिए एक सक्रिय सरकार की जरूरत है। यहां का दुर्भाग्य है कि 34 वर्ष में भी राज्य सरकार विकास नहीं कर सकी। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच साल में ही विकास की ऐसी गंगा बहाई कि आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा शासित राज्य विकास की आज मिसाल हैं। गुजरात तो विकास दर में सबसे ऊपर होकर आज चीन व योरोप के दर्जे में है। तृकां–कांग्रेस जोट की आलोचना करते हुए कहा कि ये नेता तो आपस में ही कलह कर रहे हैं। एक के खिलाफ दूसरा दल डमी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है। यदि यह जोट सरकार बनाती है तो वह विकास नहीं कर पाएगी। टू–जी स्पेक्ट्रम घोटाला के प्रसंग में कहा कि इस मामले में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए का घपला हुआ है। इस राशि का एक फीसदी यानी कि 1700 करोड़ रुपए मिल गए हैं। लेकिन बाकी रकम से तो डुवार्स क्षेत्र का संपूर्ण विकास संभव था। स्कूल, कॉलेज, सड़क व अस्पताल बन सकते थे। केंद्र की सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसलिए वास्तविक विकास के लिए आप सब भाजपा को मत दें।

प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री तथागत राय ने कहा कि विगत बीस वर्ष से उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में तानाशाही चल रही है। लेकिन इस पर माकपा व तृकां दोनों ही मौन हैं। आज की जनसभा को गोजमुमो की केंद्रीय कमेटी के सदस्य संतोष राई, उषा लाकड़ा, भाजपा की महिला मोर्चा की आशा लाकड़ा, पीपीपी के केंद्रीय सचिव जयनारायण तिर्की, राज्य अध्यक्ष गणेश एक्का व अन्य ने संबोधित किया।

वहीं उत्तर दिनाजपुर में भाजपा नेता श्री अरूण जेटली ने कहा कि वाममोर्चा सरकार ने 35 साल में पश्चिम बंगाल को बदहाल कर दिया। केन्द्र सरकार तो भ्रष्ट व घोटालेबाज सरकार है। भाजपा के केन्द्रीय नेता अरूण जेटली ने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार नेपाल दल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसी सरकार को पांच साल काम करने का मौका मिलता है तो बेहतर काम करती है। अगर दस साल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा कर जाती है। मगर वाममोर्चा सरकार को 35 साल सरकार चलाने का मौका दिया। इतने दिन में राज्य की काया पलट हो जानी चाहिए, ताज्जुब है कि बंगाल बदहाल हो गया। कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस की क्या बात करें केन्द्र में 60 साल तक शासन किया, मगर कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस के कार्यकाल में एक के बाद एक घोटाले हुए। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता इतिहास लिखेगी। वाम सरकार को हटा कर नई सरकार बनाएगी।

इसलिए जनता को सोचना होगा कि वह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार बनायेगी अथवा भाजपा की सरकार बनायेगी। कांग्रेस–तृकां की सरकार बनेगी तो राज्य का कोई विकास नहीं होगा। भाजपा की सरकार बनी तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सुशासन की सरकार बनेगी। विकसित राज बनेगा। बिहार का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि एनडीए ने पांच साल में बिहार में सुशासन व विकसित सरकार देकर यह साबित कर दिया है। गुजरात में भी ऐसा ही है। सभा को बिहार के किशनगंज जिला के ठाकुरगंज के पूर्व विधायक सिकन्दर सिंह ने भी संबोधित किया।

बंगाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ : नरेन्द्र मोदी

गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने वाम मोर्चे पर पश्चिम बंगाल में उसके 34 सालों के शासन काल के दौरान विकास कार्य नहीं होने एवं कोई उद्योग स्थापित नहीं करने का आरोप लगाया।

गत 16 अप्रैल को जलपाईगुड़ी जिले के मदारीहट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनोज टिक्का के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल के बहुत से लोग गुजरात के विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं। ये लोग गुजरात इसलिए जाते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उद्योग नहीं होने के चलते उन्हें यहां नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल के जिलों और दार्जिलिंग में चाय के कई बागान हैं, लेकिन राज्य सरकार इन क्षेत्रों में किसी प्रकार के कल–कारखाने लगाने में नाकाम रही। श्री मोदी ने कहा कि चाय बागानों में काम करने वाले यहां के कामगारों की स्थिति काफी दयनीय है। उन्हें सरकार की ओर से किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा एवं शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती और न ही इन्हें जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सुविधा मुहैया है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कई गांवों में बिजली एवं सड़क की सुविधा नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, तो वह राज्य की जनता के लिए काम करेंगे। ■

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनशन पर

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा ने 23 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी असहयोग कर रहे हैं और उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में बाधा डाल रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा, 'कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सहयोग नहीं दिए जाने के कारण भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली की रैलियों सहित कई तय रैलियां स्थगित करनी पड़ी हैं। अधिकारियों के बीच समुचित तालमेल के अभाव में दो चरणों के मतदान से पूर्व हमारे कई नेताओं की जनसभाएं विलंब से हो पाईं।'

उन्होंने उत्तरी 24 परगना के अतिरिक्त जिलाधिकारी रणधीर कुमार और हावड़ा जिले के उलूबेरिया थाना प्रभारी को उनके 'असहयोग' के लिए तुरंत निलंबित करने की मांग की। ■

बंगाल में लेफ्ट के कुशासन से मुक्ति का आंदोलन

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को 35 साल के वाम मोर्चे के कुशासन से मुक्ति दिलाने वाला स्वतंत्रता आंदोलन करार दिया है। उन्होंने विकास विरोधी वाम मोर्चा सरकार को जमकर कोसा।

यहां गुजरात चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक सेमिनार में मोदी ने कहा कि बंगाल में उन्होंने जो कुछ देखा, वह हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि वाम मोर्चे के दमनपूर्ण शासन से आजादी पाने का एक स्वतंत्रता आंदोलन है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोग सिर्फ भोजन के लिए आलू व अन्य सब्जियां सीधे किसानों से खरीदते हैं जबकि गुजरात में आलू उगाया जाता है जो कनाडा के बाजारों में बेचा जाता है जहां से चिप्स बनाकर पूरी दुनिया में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि जलपाईगुड़ी में लोगों की आवश्यकता पूर्ति के बाद जो आलू बचता है वह नष्ट कर दिया जाता है। मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि वाम मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में राज्य में कोई भी कारखाना स्थापित नहीं हुआ है। यहां विकास कार्य एकदम ठप हैं। उन्होंने कहा था कि बंगाल के तमाम लोग गुजरात के कारखानों में नौकरी कर रहे हैं क्योंकि यहां बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। राज्य में नौकरी न मिलने से इन लोगों को गुजरात आना पड़ा। मदारीहट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मदन टिक्का के पक्ष में चुनावी सभा में बोलते हुए मोदी ने कहा था कि लेफ्ट फ्रंट औद्योगिक मोर्चे पर एकदम विफल रहा है। उत्तरी बंगाल के दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में कई चाय बागान हैं लेकिन वाम मोर्चा यहां कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सका। उन्होंने आरोप लगाया कि चाय बागान में काम कर रहे मजदूरों की स्थिति दयनीय है। ■

देश में लूट मची है : नितिन गडकरी

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में लूट मची है। जो मंत्री जितना चाह रहा है जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहा है। टूजी स्प्रेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर श्री गडकरी ने यूपीए सरकार की जमकर खिंचाई की। गांधीजी ने आजादी के बाद रामराज का सपना देखा था, लेकिन हालात यह है कि भ्रष्टाचार की एक से एक कहानियां दिख रही हैं।

महंगाई, भ्रष्टाचार और कालेधन की वापसी को लेकर भाजपा ने राजधानी रायपुर में हुंकार भरी। सप्रे शाला मैदान में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने केंद्र की यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों व भ्रष्ट प्रशासन के कारण ही महंगाई पनप रही है। टीवी पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार व घोटालों की लोकप्रिय धारावाहिक चल रही है। भाजपा ही भविष्य बदल सकती है। भाजपा हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देना चाहती है। उन्होंने जनता से कहा कि हमें ताकत दीजिए। कालेधन को विदेशों से वापस लाकर उसे जनता की भलाई के लिए खर्च करेंगे। श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछा कि केंद्र सरकार को विदेशों में कालाधन जमा करने वालों के नाम जाहिर करने में अड़चन क्यों है? नाम जाहिर करने से कांग्रेस का भी मुंह काला होगा, इसलिए नाम जाहिर नहीं कर रही है। श्री गडकरी ने प्रदेश की डॉ. रमन सिंह की सरकार की भी जमकर तारीफ की और नक्सलियों से प्रदेश के विकास के लिए हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार का सहयोग करने का आव्हान किया।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं की बदौलत हम सरकार बनाने में कामयाब हो पाए थे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, बचाओ देश को। जब से केंद्र में यूपीए की सरकार आई है, सरकार की अर्थव्यवस्था पर पकड़ समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से जूझते हुए भी विकास की दिशा में बढ़ने में कामयाब रहा है। छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में मॉडल स्टेट बनकर छत्तीसगढ़ खुद को प्रस्तुत करेगा। ■

पृष्ठ 8 का शेष...

लाख की अपनी मूर्तियां लगवाई हैं। राज्य में बिजली आती नहीं है अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बहन जी लाल बत्ती में और जनता मोमबत्ती में जीवन बिता रही है। रैली को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर और सह प्रभारी एवं सांसद श्री राधामोहन सिंह ने भी संबोधित किया। रैली में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट समैया, प्रदेश महिला अध्यक्ष मधु मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अरूण कुमार सिंह, मानवाधिकार प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री सुधीर अग्रवाल, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता नेपाल सिंह, राज्य के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हुकूम सिंह, राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रधान, मेरठ से लोकसभा सदस्य श्री राजेन्द्र अग्रवाल और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। मेरठ मेयर श्रीमती मधु गुर्जर, उत्तर प्रदेश के भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने श्री नितिन गडकरी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ■

न राजनीति गंदी और न ही सभी नेता भ्रष्ट : सुषमा

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का कहना है कि न तो राजनीति गंदी है और न ही सभी नेता भ्रष्ट हैं। राजनीति में अच्छे नेताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ अर्से में राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं उससे जनता में एक नकारात्मक संदेश गया है। भाजपा के लिए भ्रष्टाचार और महंगाई दो प्रमुख मुद्दे हैं जो उत्तर से दक्षिण तक आम जनता के बीच चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिला है। केरल और तमिलनाडु में सघन प्रचार अभियान के बाद दिल्ली लौटीं श्रीमती स्वराज ने 'नईदुनिया' से पांच राज्यों के चुनाव, भ्रष्टाचार, अण्णा हजारे का आंदोलन, लोकपाल बिल और मध्य प्रदेश के साथ केंद्र सरकार के स्तर पर हो रहे भेदभाव जैसे मुद्दों पर बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंशः

भ्रष्टाचार को लेकर अण्णा हजारे की मुहिम पर भाजपा का क्या रुख है? कहा जा रहा है कि लोकपाल बिल को लागू करने के लिए जिस प्रकार से अण्णा हजारे और कुछ अन्य लोगों ने अनशन कर दबाव बनाया वह तरीका सही नहीं है, क्योंकि विधेयक संसद बनाती है?

भ्रष्टचार के मुद्दे पर भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है। पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सांसद घूस कांड का मुद्दा भाजपा ने संसद के भीतर और बाहर जोर शोर से उठाया था। देश की जनता को बताया था कि कैसे मनमोहन सरकार ने पैसे के बल पर विश्वासमत हासिल किया। विकीलीक्स के खुलासों ने हमारी बात को सही साबित किया। इसलिए हम पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो या फिर टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला या फिर सीवीसी के पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति का मामला हो। भाजपा और राजग ने इन सभी घोटालों को राष्ट्रीय स्तर पर जोर–शोर से उठाया। अब देश की जनता के बीच भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

अण्णा हजारे और तमाम सामाजिक संगठन भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर यूपीए सरकार पर एक कठोर कानून बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। हम जनता की इस पहल के साथ हैं। जहां तक रहा सवाल अण्णा हजारे के आंदोलन का तो आंदोलन करने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है। अण्णा को भी। लोकपाल विधेयक अंततः संसद से ही पारित होगा।

कुछ दल और नेताओं को इस बात पर आपत्ति हो रही है कि लोकपाल विधेयक के मसौदे के लिए बनी समिति में विपक्षी दलों के सदस्यों को नहीं रखा गया है? क्या भाजपा इस विधेयक का समर्थन करेगी?

अच्छा होता समिति में विपक्षी दलों के सदस्यों को भी रखा जाता। उनके विचार भी तुरंत मिल जाते, लेकिन यह विषय विवाद का नहीं है कि प्रारूप बनाने वाली समिति में कौन है और कौन नहीं। मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून बनाने का। भाजपा एक प्रभावी विधेयक चाहती है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि एक प्रभावी प्रारूप सामने आएगा। संसद में उस पर चर्चा होगी। लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित संयुक्त समिति की बैठक में मसौदे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हम प्रारूप का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा देखेगी कि लोकपाल विधेयक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था है या नहीं। यदि प्रभावी व्यवस्था होगी तो हम जस का तस समर्थन कर संसद से पारित करवाने में अपना सहयोग देंगे। यदि

हमें लगेगा कि विधेयक प्रभावी नहीं है तो हम सुझाव देकर उसमें संशोधन करवाएंगे। हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार को रोकना है, विधेयक को नहीं।

एक बात यह भी कही जा रही है कि भाजपा ने छह साल केंद्र में राजग सरकार चलाई, लेकिन तब भाजपा ने लोकपाल की बात नहीं की?

नहीं यह कहना गलत है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने लोकपाल की दिशा में कुछ नहीं किया। सच यह है कि राजग सरकार ने अपने कार्यकाल में लोकपाल विधेयक पारित करवाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी रखा जाए। लोकपाल विधेयक के प्रति भाजपा का रुख हमेशा से सकारात्मक रहा है।

सभी नेताओं को भ्रष्ट कहे जाने पर लालकृष्ण आडवाणी सहित कई दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपका क्या मानना है?

मैं मानती हूं कि न तो राजनीति गंदी है और न ही सभी नेता भ्रष्ट हैं। राजनीति में अच्छे नेताओं की भी कमी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ अर्से में राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए हैं उससे जनता में एक नकारात्मक संदेश गया है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, सांसद घूस कांड, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसने रही सही कसर पूरी कर दी।

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर लोक लेखा समिति (पीएसी) और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में जांच के दायरे को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। पीएसी की बैठक में कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों ने हंगामा तक कर दिया? कहा जा रहा है कि कोई एक जांच करे वरना जांच में टकराव होगा। आपका क्या मत है?

पीएसी की बैठक में हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय समितियां संसद का ही प्रतिबिंब होती हैं। समितियों के सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। कई बार अच्छा विधेयक बने इसके लिए सत्तापक्ष के सदस्य भी अपनी सरकार से उलट सुझाव रखते हैं, तो विपक्षी सदस्य अच्छे सुझावों का खुलकर समर्थन करते हैं। हाल के कुछ वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्तियों और कार्यप्रणाली को लेकर विवाद हुए हैं, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। संसदीय समितियों में भी दलगत विरोध से न केवल संसदीय कामकाज प्रभावित होता है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा भी घटती है। मैं मानती हूं कि स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर पीएसी और जेपीसी की भूमिका में कहीं कोई टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों समितियों का अपना–अपना कार्यक्षेत्र है, दायरा है। लोकसभाध्यक्ष इस मुद्दे पर अपना निर्णय भी दे चुकी हैं, इसलिए इस विषय पर अब और अधिक विवाद नहीं होना चाहिए।

केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम सहित भाजपा ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जबकि इन राज्यों में भाजपा का कोई खास जनाधार नहीं है। विरोधी भाजपा को उत्तर भारत की पार्टी कहते हैं?

जो लोग भाजपा को केवल उत्तर भारत की पार्टी मानते हैं, उन्हें अपना यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए। कर्नाटक में भाजपा की सरकार पहले से ही है। जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं यह ठीक है वहां भाजपा का अधिक जनाधार नहीं है लेकिन इस बार के परिणाम हमारे विरोधियों के लिए चौंकाने वाले होंगे। भाजपा के मतों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। असम में हम सरकार बना सकते हैं। केरल और तमिलनाडु में हमें उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला है। जनता भाजपा की तरफ एक तीसरे विकल्प के रूप में आशाभरी नजरों से देख रही है। घोटालों और महंगाई ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया है और इसका असर चुनाव में भी दिखाई दिया।

मध्य प्रदेश सरकार किसानों के मुआवजे, कोयला आवंटन, बिजली आपूर्ति, खाद्य योजना आदि योजनाओं में केन्द्र की यूपीए सरकार पर भेदभाव के आरोप लगा रही है। आपके नेतृत्व में भाजपा सांसदों ने धरना भी दिया था। आपका क्या कहना है?

मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दे हमेशा से मेरी प्राथमिकता में ऊपर रहे हैं, क्योंकि मैं लोकसभा में विपक्ष की नेता हूं और विदिशा से सांसद हूं। पिछले सत्र में भी हम मध्य प्रदेश के हक के लिए लड़े थे और यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार सहन नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से केन्द्र सरकार पर हक के लिए दबाव बनाएंगे। ■

नितिन गडकरी का एक अलग चेहरा

भाजपा अध्यक्ष के लिए अक्षय ऊर्जा का प्रसार एक जूनून

&fç;k lgxy

jktनीति ही भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आप यकीन करें या नहीं, वे अक्षय ऊर्जा के भी प्रबल पैरोकार हैं। जैव ईंधन से हर महीने 36 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। 500 करोड़ रुपये के उनके 'पूर्ति समूह' का मुख्य आधार अक्षय ऊर्जा ही है। इसके प्रति उनका जुनून देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का संचालन करने के जुनून से कम प्रबल नहीं है। वे राजनीति की जितनी रैलियां कर चुके हैं जैव तकनीकि पर उतनी ही गोष्ठियों को संबोधित कर चुके हैं।

बैगी पैंट और रंग बिरंगी कमीज में वे कहीं से भी नेता नजर नहीं आते। वे कहते हैं, ''मैं कुर्ता पाजामा नहीं पहनता क्योंकि मैं पेशेवर नेता की तरह नहीं दिखना चाहता हूं। मैं दिखावटी आदमी नहीं हूं। मैं जैसा दिखता हूं वैसा ही हूं। मैं जा कुछ कहता हूं, वही करता हूं।'' वे भाजपा के दूसरी पांत के एकमात्र नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है, ''मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है सामाजिक विकास। अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो हम सरकार के माध्यम से योजनाएं लागू करेंगे। अगर विपक्ष में होगे तो निजी प्रयासों के जरिए काम करेंगे।''

उनके कारोबार का साम्राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, भंडारा और वर्धा जिलों में फैला है। यह इलाका किसानों की आत्महत्या के लिए कुख्यात रहा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पूर्ति समूह में 4,000 शेयरधारक हैं, जिनमें अधिकांश किसान हैं। समूह की तीन चीनी मिलें हैं, जो न सिर्फ चीनी का उत्पादन करती हैं, बल्कि इसके उप–उत्पादनों–छोआ और गन्ने

की खोई का चूरा से इथनॉल और शराब भी बनाती है। वे कहते हैं, ''इथनॉल किसानों का उत्पादित किया स्वच्छ ईंधन है। यह आयतित तेल का, जिसका मुनाफा आतंकवादियों के पास जाता है, विकल्प है। जैव–डीजल के इस्तेमाल से किसानों और आदिवासियों को फायदा होता है।'' धान उत्पादक जिले चंद्रपुर में उनका एक कारखाना आठ मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसमें धान की भूसी से बिजली पैदा की जाती है। वे बताते हैं, ''मेरी कोशिश है कि कृषि का विस्तार ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में हो।'' भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसने जैव–ईंधन के प्रसार के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है।

इस 53 वर्षीय पार्टी अध्यक्ष की अक्सर आलोचना होती रहती है कि वे इतना ज्यादा 'राजनीतिक' नहीं है कि मुख्यधारा की पार्टी का नेतृत्व कर सकें। वे कहते हैं, ''मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। यह गुरूर की बात नहीं है। कृपया इसका गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन मैंने अपनी राह और लक्ष्य तय कर लिया है और मैं उस पर आगे बढ़ूंगा।'' फिर वे मुस्कराते हुए कहते हैं ''अगर कुछ करने की इच्छा है तो उसका रास्ता भी निकल आता है। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर केवल सर्वे, सेमिनार और समितियां ही होती हैं'' उनका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ स्पष्ट है, जो समितियों के गठन के प्रति ज्यादा तत्पर रहते हैं। दिसम्बर 2009 में भाजपा का अध्यक्ष पद

संभालने के तुरंत बाद उन्होंने पार्टी के हर नेता से विकास की कम से कम एक योजना को हाथ में लेने के लिए कहा। उनकी कोशिश एक गैर–सरकारी संगठन की कार्यशौली वाले शासन को बढ़ावा देने की है। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों ने उनकी बात पर अमल किया है तो वे कंधे झटक देते हैं, वे कहते हैं, ''मैं राजनीति को सामाजिक–आर्थिक सुधार के एक साधन का रूप देना चाहता हूं। राजनीतिक का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होना चाहिए। बल्कि वह विकासपरक होनी चाहिए।'' वे एक मिसाल देते हुए बताते हैं कि किस तरह सामाजिक उद्यमशीलता का उनका ब्रांड फायदेमंद साबित होता है। उनके पूर्ति समूह ने पिछले साल अक्टूबर में राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल के प्रभाव वाले क्षेत्र भंडारा में घाटे में चल रहे चीनी के एक कारखाने को खरीदा। वह कारखाना 25 करोड़ रु. के घाटे में था। पूर्ति समूह ने इसके लिए 14.10 करोड़ रु. दिए और वादा किया कि जब यह चलने लगेगा तो इलाके के 5,000 युवकों को रोजगार मिलेगा और 2 लाख गन्ना किसानों को काम मिलेगा। इसके उद्घाटन के तुरंत बाद भाजपा ने राकांपा के गढ़ में जिला परिषद के दो चुनाव जीते। गडकरी कहते हैं, विकास की राजनीति हमेशा लाभ पहुंचाती है।

भाजपा जिसे अक्सर पुराने राग अलापने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है, उसके मामले में यह बात ताजा हवा के झोंके की तरह लगती है वे एकदम साफ और मुद्दे की बात करते हैं जैसे भारत के पास परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का भंडार नहीं है, जिस तरह चीन 18,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करता है। उसी तरह भाजपा को भी अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने की जरूरत है। यह उनका सिर्फ जबानी जमा खर्च का मामला नहीं है बल्कि जैव–ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने की भी कोशिश की है।

मुंबई में गडकरी के दफ्तर में उनकी मेज पर लिखा वाक्य ''मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो काम को अंजाम दे सकते हैं''– स्पष्ट संकेत देता है, 1995–1999 में महाराष्ट्र में शिवसेना–भाजपा शासन के दौरान जब वे लोकनिर्माण मंत्री थे तब उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करके अपनी खास पहचान बनाई थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने कुल 55 फ्लाईओवर बनवाए जिनके चलते उन्हें 'पुलकरी' कहा जाने लगा था। मुंबई–पुणे एक्सप्रेस–वे के निर्माण के पीछे भी उनका हाथ रहा है। वे खुश होकर बताते हैं ''आज इसका इस्तेमाल रतन टाटा से लेकर अमिताभ बच्चन तक कर रहे हैं।''

उन्होंने मनमोहन सिंह–मोंटेक अहलूवालिया के लोकप्रिय बनाए पीपीपी मॉडल को बहुत पहले ही शुरु कर दिया था। वे बताते हैं, ''मंत्रालय के पास सिर्फ 1,500 करोड़ का बजट था और 12,500 करोड़ की स्वीकृत परियोजनाएं अटकी पड़ी थीं। इसलिए बजट की कमी के कारण काम लटका पड़ा था। तब यह पीपीपी मॉडल प्रचलित नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप किस्तों पर फ्रिज खरीद सकते हैं तो पुल, सुरंग और सड़कें क्यों नहीं बनवा सकते।'' पैसे जुटाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएमआरडीसी) का गठन किया और देश में शायद पहली बार एक सरकारी कंपनी ने बुनियादी परियोजनाओं के लिए खुले बाजार के जरिए पैसा जुटाया। उनका दावा है कि उन्होंने शेयरों से 5,000 करोड़ रुपये जुटाए और 8,000 करोड़ रु. की योजनाएं पूरी कीं। बाद में शिवसेना के साथ उनका टकराव भी हुआ। शिवसेना चाहती थी कि मुंबई–पुणे एक्सप्रेस–वे की परियोजना एक निजी कंपनी को दी जाए जिसने 3,600 करोड़ रु. का बजट दिया था। गडकरी ने यह काम एमएसआरडीसी को सौंप दिया जिसने इसे 1,650 करोड़ रु. की लागत से ढाई साल में पूरा कर दिया।

लोकनिर्माण मंत्री के तौर पर गडकरी ने अपने को बुनियादी काम तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने दफ्तर के फर्नीचर को नया रूप दिया, हर कर्मचारी के लिए कम्प्यूटर का आर्डर दिया और दफ्तर को सरकारी दफ्तर की जगह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के दफ्तर जैसा आकर्षक बनावाया। शायद वे अपनी पार्टी को भी कुछ ऐसा ही रूप दे सकें। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, ''मैं प्रोटोकॉल पसंद नहीं करता। मेरी अगवानी के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं आता। मैं भी किसी की अगवानी के लिए एयरपोर्ट नहीं जाता। मैंने कभी अपना या किसी और का पोस्टर नहीं लगाया।'' दिल्ली में उनकी अलमारी में बराक ओबामा, दलाई लामा और एग्रो–बैंकिंग पर लिखी पुस्तकें लगी हुई हैं। उन्हें एक्शन वाली फिल्में अच्छी लगती हैं। खासकर अमिताभ बच्चन की जंजीर और दीवार। वे कहते हैं, मैं ऐसी फिल्में पसंद करता हूं जिनमें कोई संदेश हो जैसे 'तारे जमीं पर' और 'स्वदेश'।''

गडकरी अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्वीकार करते हैं कि यह मुश्किल काम है। वे कहते हैं, ''मैं जो देखता हूं, खा लेता हूं। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं कितना सफल हो पाऊंगा।'' ■

(इण्डिया टुडे में प्रकाशित आलेख का सम्पादित पाठ)

व्यापारिक समझौते राष्ट्रहित में नहीं : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा गुरूवार, 21 अप्रैल 2011 को जारी प्रेस वक्तव्य

संप्रग सरकार द्वारा सभी हिस्सेदारों के साथ उचित परामर्श किये बिना विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि/सी.ई.सी.ए/सी.ई.पी.ए आदि व्यापारी समझौते करने सम्बंधी कार्यवाही की भाजपा निन्दा करती है। संप्रग सरकार जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के साथ पहले ही व्यापक आर्थिक सहभागिता करार 'कम्परिहेन्सिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (सीईपीए), कर चुकी है। इसमें आसियान और थाईलैंड के साथ वस्तु विनिमय करार भी किये हैं। यूरोपीय यूनियन और ईएफटीए के साथ सीईपीए करने हेतु बातचीत कर रही है। इन सभी करारों से भारत की समग्र विकास रणनीति, विशेषकर रोजगार निर्माण, आयात, निर्यात एवं खेती पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह तथ्य भी निन्दनीय है कि ऐसे करार, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर लम्बे समय तक बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, पर मंत्रिमंडल में भी चर्चा नही की गई, संसद और विपक्षी पार्टियों की बात तो दूर रही।

संप्रग सरकार डब्ल्यू.टी.ओ. के अन्तर्गत बहुपक्षीय समझौते का पालन नहीं कर रही है और दोहा राउंड में सौदेबाजी सम्बंधी अपनी शक्ति को संकुचित कर रही है। यहां तक कि 2010–11 के आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ 186) मे द्विपक्षीय समझौतों में नई सनक के बारे में सरकार को चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है ''कुछ मामलों में भागीदार देशों को होने वाले लाभ बहुत अधिक हैं और भारत को होने वाला शुद्ध लाभ बहुत थोड़ा अथवा नगण्य है। एफआईएएस से भी एक नये प्रकार का इन्वर्टिड डयूटी स्ट्रक्चर बन जायेगा। इससे स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन नही मिलेगा क्योंकि यह एफटीए आयातों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। एफटीएएस/सीईसीएएस से सम्बंधित नीति में घरेलू क्षेत्र की विशिष्ट बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफटीएएस अधिक संख्या में न हो''।

> ***संप्रग सरकार द्वारा सभी हिस्सेदारों के साथ उचित परामर्श किये बिना विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि/सी.ई.सी.ए/सी.ई.पी.ए आदि व्यापारी समझौते करने सम्बंधी कार्यवाही की भाजपा निन्दा करती है।***

कुछ अति महत्वपूर्ण मुददे इस प्रकार है:

पहला, संप्रग सरकार 2003 में कानकुन डब्ल्यू.टी.ओ. मिनिस्टीरियल कान्फ्रेंस में सिंगापुर मुददों को हटाने के बाद भारत को हुए लाभों को गंवा रही है। सरकारी प्राप्तियों, निवेशों और स्पर्धा की नीतियों को दोहा राउंड से हटा दिया गया है। वास्तव में अब सरकार लाभों को व्यर्थ जाने दे रही है और विकसित देशों के दबाव में आ रही है और सीईसीए/सीईपीए के माध्यम से इन सभी मुददों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

दूसरा, कृषि और स्वास्थ्य प्रमुखतः राज्यों का विषय है। संप्रग सरकार राज्य सरकारों से सलाह मशविरा किये बिना एफटीए पर बातचीत कर रही है और इस तरह वह संविधान द्वारा गारंटीशुदा संघीय ढांचे को अनदेखा कर रही है।

तीसरा, संप्रग सरकार द्वारा एफटीए के बारे में चल रही वार्ता पारदर्शी नहीं है और वह गोपनीय है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, बातचीत सम्बंधी पाठ और संगत जानकारी लोगों को नही दे रही है। राजग सरकार ने सभी पार्टियों से सलाह मशविरा किया था और अपनी पहल पर इस पर संसद में भी बहस करवाई थी। संप्रग सरकार इस प्रयोजनार्थ बनाये गये एक निकाय अर्थात् टीईआरसी में बातचीत कर रही है। इस निकाय में गैर–निर्वाचित प्रतिनिधि बहुसंख्या में है।

भाजपा मांग करती है,

1. एफटीएएस/सीईसीएएस पर चर्चा हेतु सर्वदलीय बैठक हो।
2. सम्पंन हुए और वार्ता अधीन सभी एफटीएएस पर संसद में व्यापक चर्चा कराई जाये।
3. अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के अनुसमर्थन के लिये एक विधान पेश किया जाये ताकि उन पर संसद की अनुमति ली जा सके।
4. एफटीएस/सीईसीएएस, विशेषकर यूरोपीए संघ–भारत के बारे में बातचीत का पाठ और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को तुरन्त सार्वजनिक किया जाये। ■

हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय व साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक : प्रो. प्रेम कुमार धूमल

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की हिमाचल राजनीति में गैर–कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों में सबसे लम्बी अवधि तक शासन करने की नई परम्परा की नींव रख दी है। वर्तमान दूसरी शासनावधि में वह पहले ही अब तक तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं। उनकी अपनी इस दूसरी पारी में प्रो. धूमल ने राज्य में कई प्रकार की प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्त किए हैं, जबकि यह स्थिति तब है जब कांग्रेस–नीत–यूपीए सरकार इस प्रदेश पर उतनी मेहरबान नहीं है जितनी वह कांग्रेसी प्रदेश सरकारों पर रहती है। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत, निजी समझदारी और सम्पर्कों से तेजी से विकास की गति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आज, हिमाचल प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे बढ़ा दिखाई पड़ता है। अभी लगभग 10 दिन पूर्व जब प्रो. धूमल दिल्ली में थे तो भाजपा के साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अम्बा चरण वशिष्ठ ने उनसे बातचीत की। यहां इस वार्ता के प्रमुख उद्धरण प्रस्तुत हैं:–

अपनी दूसरी पारी में हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में आपने चौथे वर्ष में कदम रखा है। आपको कैसा महसूस होता है?

इन सभी वर्षों में लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने पर विनम्र और हर्ष का मिलाजुला अहसास होता है। लोगों के प्यार, स्नेह और उदार समर्थन से ही मुझे उनकी सेवा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। पार्टी और जनता मेरी ताकत के दो स्तंभ रहे हैं।

इस बार आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं?

पिछली विधानसभा चुनावों के समय हमने जितने भी लोगों से वायदे किए थे, वे लगभग पूरे किए गए हैं। शेष शासनावधि में तो हम इससे भी कहीं आगे बढ़ जाएंगे। हम लोगों की सेवा में और भी ऊंचे से ऊंचे स्तर तक कई बड़े मील के पत्थर गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में त्वरित एवं चहुंमुखी विकास करने में हम कई क्षेत्रों में पथ–प्रदर्शक बनकर सामने आए हैं। अनेकों प्रतिष्ठित एजेंसियों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण इस बात का साक्षी है। पिछले वर्ष के 'इण्डिया टूडे' के सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को 'स्टेट आफ स्टेट्स' एवार्ड में सर्वोत्तम प्रदेश का दर्जा दिया गया है। हम समग्र प्रदर्शन, शिक्षा, माइक्रो–इकॉनामी और निवेश में सबसे ऊपर रहे हैं। 'आउटलुक' और 'आईबीएन–7' इलेक्ट्रानिक चैनलों ने हिमाचल को समग्र प्रदर्शन, निर्धनता उन्मूलन और शिक्षा सुधार में सर्वोत्कृष्ट मानते हुए 'डायमण्ड स्टेट एवार्ड' प्रदान किया है। कृषि विकास में असाधारण नीति प्रोत्साहन और प्रदर्शन के मामले में 'एग्रीकल्चर टूडे' पत्रिका ने 'स्टेट एग्रीकल्चर लीडरशिप एवार्ड 2010' प्रदान किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हिमाचल सबसे ऊपर रहा है। यह सभी इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार गरीबों तथा वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितनी अधिक चिंतित रहती है।

आपके वर्तमान शासनकाल के शेष दो वर्षों की क्या योजनाएं हैं?

हम चाहेंगे कि हमारी उपलब्धियों के फल और अधिक संचित हों और विकास की गति और अधिक तेज हो। मेरी सरकार हिमाचल की ठोस नींव रख कर प्रत्येक वर्ग के लोगों के कल्याण एवं बेहतरी को सुनिश्चित करेगी। मेरा संकल्प है कि लोगों को पर्याप्त रोजगार और स्व–रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और

आत्म–सम्मान का जीवन प्राप्त हो।

और कोई अभूतपूर्व बात?

बहुत सी बातें हैं। हमने 350 करोड़ रूपए की प. दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना की शुरूआत की है जिससे 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ यथार्थ खेती नीतियां अपनाते हुए नकद फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी की धनराशि से 321 करोड़ रूपए की 'क्राप डाइवर्सिफिकेशन प्रोमोशन प्रोजेक्ट' की शुरूआत की जा रही है। 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और जनजाति आबादी वाले गांवों के एकीकृत विकास के लिए एक नई मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत 136 गांवों में की जा रही है जिसे सड़क नेटवर्क, जलापूर्ति, सेनीटेशन और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को एक समन्वित ढंग से लागू किया जाए। जिन छात्रों को बस से 5–8 कि.मी. की दूरी तय कर स्कूल पहुंचना होता है, उनके लिए 200 रूपए की मासिक छात्रवृत्ति दी गई है और जिन्हें इससे अधिक दूरी तय करनी होती है, उन्हें 300 रूपए दिए जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पर्यटन सम्बन्धी इफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 428 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी है। ई–समाधान प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही विभिन्न सरकारी प्रभारों और बकाया राशि के लिए आनलाईन भुगतान करने की शुरूआत हो चुकी है। 'एग्रीसनेट' पोर्टल का विकास हुआ है ताकि किसानों को आनलाइन विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त हो सके।

हम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं ताकि निर्धारित समय के अन्दर नागरिकों को कुछेक लोक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

आपकी महत्वाकांक्षी मनाली-लेह रेलवे परियोजना की आज की स्थिति क्या है?

यह परियोजना देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैंने इस विषय को प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के साथ उच्चतम स्तर पर बात की है और उन्हें बताया है कि जिस प्रकार से चीन ने तिब्बत की हमारी सीमा तक रेल, सड़क और वायु सेना स्टेशन बना कर धमकी भरे कार्य किए है, उन्हें देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इस कार्य में सफल नहीं होंगे तब तक हम केन्द्र सरकार के साथ पर इस परियोजना के लिए लगातार जोर डालते रहेंगे। मैंने अपनी ओर से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण रेल–लिंक की अनिवार्यता पर केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया है। अब आगे जो कुछ करना है वह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है।

हिमाचल अब पिछड़ा राज्य नहीं रह गया है। अब यह विकास के मामले में विकसित राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। आज की क्या स्थिति है?

आपने ठीक कहा। हमने हिमाचल को विकास के कई दायरों को सर्वोकृष्ट बनाया है। आज यह न केवल पर्वतीय राज्यों के लिए मॉडल की भूमिका बन गया है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए यह मॉडल बन गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 58,493 रूपए हो गई है और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 52,428 करोड़ रूपए तक जा पहुंचा है। साक्षरता प्रतिशत 86 प्रतिशत तक जा पहुंचा है जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वर्तमान सरकार ने जो काम किए है, ये उनकी एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करता है।

यह आम धारणा है कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन और सरकार के बीच अर्न्तद्वंद्व बन जाता है। हिमाचल में क्या स्थिति है?

यह हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं है। संगठन और सरकार पूरी तरह से समझ और समन्वय से काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन और कार्यकर्ता हमारी सरकार की अपार शक्ति है। लोगों के समर्थन से ही हम इतना अधिक और इतनी तेजी से सब कुछ कर पाए हैं।

सरकार और पार्टी में महिलाओं और युवाओं को कितना पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है?

सरकार के प्रत्येक भाग में महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है। सत्ता में आने के तुरंत बाद ही हमने पंचायती राज संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दीं। आपको यह जान कर खुशी होगी कि पिछले वर्ष के चुनावों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं इन संस्थानों में चुनी गईं।

कुछ समय पूर्व हुए नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों में पार्टी की क्या स्थिति रही?

भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने इन चुनावों में 60 प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं।

क्योंकि प्रदेश में एक दल की सरकार है और केन्द्र में दूसरे दल की तो क्या आपको इससे कुछ बाधा महसूस हो रही है?

हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि राज्य को केन्द्र से उसका वैध हिस्सा प्राप्त हो। बहुत हद तक मुझे इसमें सफलता भी मिली है। कुछ मामले बकाया भी है, जैसे श्री अटल

बिहारी वाजपेयी वाली एनडीए सरकार द्वारा मंजूर औद्योगिक पैकेज को समाप्त किया गया, फिर मनाली–लेह रेलवे लाइन, जिनमें यूपीए सरकार ने राज्य के लिए उदार सहायता नहीं दी है। इन मुद्दों से लोग बहुत आक्रोशित हैं।

श्री अटल बिहारी सरकार द्वारा मंजूर विशेष औद्योगिक पैकेज में कटौती करने से राज्य के औद्योगिक विकास पर कितना असर पड़ा है?

इस पैकेज ने राज्य के औद्योगिक विकास की गति को बहुत प्रोत्साहन दिया था। लगभग सभी बड़ी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने यहां अपनी इकाईयां स्थापित की हैं। युवाओं को रोजगार मिले। परन्तु इसमें कटौती करने से बहुत हद तक राज्य पर दुष्प्रभाव पड़ा है। हम अपनी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि औद्योगिक प्रगति की गति कम न होने पाए। हम उद्यमियों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, परियोजनाओं की तेजी से स्वीकृति, पर्याप्त रूप से सस्ती बिजली के साथ ही साथ पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन प्रदान कर सर्वोत्कृष्ट औद्योगिक वातावरण बनाने में तत्पर हैं। इससे लाभ हुआ है। ■

जम्मू–कश्मीर

महंगाई व भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष हेतु कटिबद्ध हों महिलाएं : स्मृति ईरानी

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी ने 25–26 अप्रैल 2011 को जम्मू–कश्मीर राज्य का दौरा किया। श्रीमती ईरानी ने वहां सुन्दरबन में एक महिला रैली को सम्बोधित किया जो बढ़ती हुई महंगाई और राष्ट्र की जड़ों को खोखला करते भ्रष्टाचार के विरूद्ध आयोजित की गई थी। महिला मोर्चा अध्यक्षा ने महिलाओं का आहवान किया कि वे महंगाई और भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक लम्बे संघर्ष के लिये कटिबद्ध हो जायें क्योंकि जब तक महिला वर्ग इस के विरूद्ध खड़ा नहीं होगा तब तक कांग्रेस नीत यूपीए तथा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की नींद नहीं खुलेगी।

श्रीमती ईरानी ने महिलाओं के विरूद्ध प्रतिदिन बढ़ती हिंसा और अन्याय के विरूद्ध भी महिला वर्ग को खड़े होने का आहवान किया। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की बढ़ती हत्याओं और बलात्कार की घटनाओं की भी निन्दा की। उन्होंने दुःख प्रकट किया कि हालांकि कांग्रेस की अध्यक्ष एक महिला हैं और दिल्ली की मुख्य मन्त्री भी एक महिला, फिर भी दिल्ली में महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं जितने कि किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं हो रहे। इस रैली में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। ■

केरल प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बी.वी. शेखर का निधन

भारतीय जनता पार्टी केरल प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बी. वी. शेखर का 20 अप्रैल 2011 को निधन हो गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने श्री शेखर के निधन पर शोक प्रकट किया है। वह केरल राज्य विधान सभा के हाल में हो रहे चुनावों में तिरूवनंतपुरम से हमारे प्रत्याशी थे। श्री शेखर लम्बे समय से पार्टी के साथ जुड़े थे। वे व्यवसाय से वकील थे और उन्होंने 1984 में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तथा अथक रूप से केरल के लोगों को पार्टी में लाने का काम किया।

उन्होंने विभिन्न पदों पर पार्टी में काम किया। वह केरल भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव थे और बहुत वर्षों तक पार्टी प्रवक्ता का कार्य करते रहे। श्री शेखर ने केरल राज्य में लोगों को पार्टी का संदेश फैला कर पार्टी–कैडर को मजबूत बनाया और पार्टी में लोगों को शामिल किया।

श्री नितिन गडकरी ने एक समर्पित एवं प्रतिबद्ध सहयोगी के निधन पर अपना गहरा हार्दिक शोक व्यक्त किया है। उनका निधन उनके परिवार तथा पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। ■

विकीलीक्स केबल्स सच्चाई हैं, असांजे की पुष्टि

&ykyÑ".k vkMok.kh

fn हिन्दू ने विकीलीक्स से लगभग 6 मिलियन शब्दों वाले 5100 भारतीय केबलों को चुनकर उन पर आधारित समाचारों और लेखों को अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत कर वास्तव में इतिहास बनाया है।

इन सभी महत्वपूर्ण रिपोर्टों के संदर्भ में दि हिन्दू के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्पादक एन. राम ब्रिटेन के नारफॉक देश में गए और वहां विकीलीक्स के एडिटर–इन–चीफ जुलियन असांजे का एक घंटे का इंटरव्यू किया जिसमें असांजे ने देश को उस सैध्दान्तिक रूपरेखा की झलक दिखाई जिसके तहत विकीलीक्स विश्व के मंच पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है और जिसने असांजे को यह सब करने के लिए प्रेरित किया।

यह इंटरव्यू दि हिन्दू में दो किश्तों में प्रकाशित हुआ है, पहला 12 अप्रैल और दूसरा 13 अप्रैल, 2011 को।

भारत से सम्बन्धित रहस्योद्घाटनों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया के संदर्भ में असांजे द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में की गई टिप्पणियां अपमानजनक हैं। दि हिन्दू और विकीलीक्स के सम्पादकों के बीच हुई सम्बन्धित बातचीत को मैं यहां शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं:

एन. रामः भारत में, शुरूआती हैरानी भरी प्रतिक्रिया के बाद, हमारे द्वारा प्रकाशित भारतीय केबलों पर सरकारी प्रतिक्रिया का स्वर – प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केबलों और अमेरिकी दूतावास तथा कांसुलेट्स द्वारा अपने स्टेट डिपार्टमेंट को भेजी गई रिपोर्टों की सत्यता पर प्रश्न उठाने या उन्हें विवादित करार देने से तय कर दिया। लोकसभा, हमारे यहां के हाऊस ऑफ कॉमन्स में 13 मार्च को उन्होंने यह कहा। उन्होंने कहा कि "सरकार ऐसे केबलों की सत्यता, विषय सामग्री या यहां तक कि इनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं कर सकती।" इससे लगता है कि भारतीय सरकार ने अन्य सरकारों से अलग, पूरी दुनिया से अलग यह रुख अपनाया है, क्या ऐसा नहीं लगता?

जुलियन असांजेः हां, ऐसा लगता है।

एन. रामः क्या आपको ऐसी प्रतिक्रिया कहीं और से भी मिली?

जुलियन असांजेः ऐसी प्रतिक्रिया कहीं और से देखने में नहीं आई, और इस प्रतिक्रिया ने मुझे परेशान किया। क्योंकि हिलेरी क्लिंटन दिसम्बर (2010) में भारतीय सरकार और अन्य अनेकों सरकारों को बताने में जुटी थीं कि ऐसी जानकारियां सामने आने वाली हैं। पिछले चार वर्षों में हमने जितने भी दस्तावेज प्रकाशित किये हैं उनकी विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल नहीं उठा, अमेरिकी दूतावास के केबलों को ही लें जिनकी पुष्टि, स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा हमारे और दुनियाभर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थानों के सैकड़ों पत्रकारों के विरूद्ध आक्रामक कार्रवाई करने से हुई है।

इसलिए मैंने कहा कि मैंने उस वक्तव्य को भारतीय लोगों को भ्रमित करने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। और यही वह बात है जो चिंताजनक है। क्योंकि यह महज एक आरोप नहीं है। यह प्रधानमंत्री के मुख से सीधे निकला हुआ है, और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या करना है। यद्यपि मैंने सुना है – मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है लेकिन आम सहमति दिखती है कि यह ठीक है – वह व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं हैं, यह दूसरे लोगों के संभवतः भ्रष्टाचार को छुपाने का सीधा प्रयास है। इससे सीधे–सीधे बचते हुए वह कह सकते थे कि 'देखिए, ये आरोप हैं। ये गंभीर हैं और हम इनकी जांच करेंगे तथा सच्चाई का पता लगाएंगे और संसद को पूरी

जनता के लिए यह दूसरा कष्टप्रद तथ्य है कि पिछले वर्षों में अमेरिका और जर्मनी जैसे अधिक शक्तिशाली देश स्विट्जरलैण्ड जैसे टैक्स हेवन्स के बैंकिंग गुप्त कानूनों में सेंध लगाकर अपनी सम्पत्ति वापस लेने में सफल रहे हैं, जबकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। इसने अभी तक सन् 2004 में पारित भ्रष्टाचार के विरूद्ध यू. एन. कन्वेंशन की पुष्टि तक नहीं की है।

रिपोर्ट देंगे।"

मुझे लगता है यदि उन्होंने यह दृष्टि अपनाई होती तो उन्होंने बड़ी सेवा की होती। अतः उन्होंने अपने हितों के विरूद्ध काम किया और अपनी पार्टी के हितों के विरूद्ध काम किया है जो असंगत है। मैं इसका अर्थ यह सुझाऊंगा कि वह जो सोचते हैं उससे अलग काम करने की उनकी आदत है – और भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की आदत से उसे छुपाने की।

एन. रामः हालांकि एक वरिष्ठ विपक्षी नेता, पूर्व उपप्रधानमंत्री और भाजपा नेता, एल.के.आडवाणी – ने मुंबई में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम में जहां मैं भी पैनल (सवाल पूछने वाले सम्पादकों का) में था – उन्होंने कहा कि ये (केबल) सत्य हैं। उन्होंने विकीलीक्स और हमारे द्वारा इन्हें प्राप्त करने की प्रशंसा की। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि ये केबल तीन हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आपने भी अपने साक्षात्कारों में कहा है लेकिन वह अपने निष्कर्षों पर स्वयं पहुंचे हैं। पहला, तथ्यात्मक है, तथ्यों पर आधारित। उन्होंने कहा है कि जहां तक मेरा मानना है ये सत्य हैं, क्योंकि ये उनके मुख्यालय के लिए थे न कि किसी और के लिए। अतः ये सत्य हैं। आगे उन्होंने कहा, कुछ व्याख्यात्मक हैं और तीसरा हिस्सा दूतावास द्वारा दी गई सलाह है।

जुलियन असांजेः हां, हां।

एन. रामः इसी प्रकार जब कांग्रेस इसके घेरे में आती है तो अन्य भाजपा नेता भी इसी स्वर में बोलते हैं। और दिलचस्प यह है कि अपनी एक चुनावी सभा में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विकीलीक्स का उपयोग किया जिसमें एक भाजपा नेता ने कहा कि "हिन्दू राष्ट्रवाद अवसरवादी मुद्दा है"।

जुलियन असांजेः हां मैंने देखा था। दिलचस्प है।

एन. रामः और उन्होंने (सोनिया गांधी) इसका उपयोग किया। वे स्वयं ही अपने हाथ स्वयं बांध रही हैं। मुझे लगता था कि मुझे इस पर आपकी तरफ से और अंदर की जानकारी मिलेगी। लेकिन आप ने कहा कि दोनों मुद्दों पर आपका लक्ष्य अचूक है। पहला, विकीलीक्स में सार्वजनिक की गई सभी सामग्री में से एक भी ऐसी नहीं है जिसमें एकदम सही के सिवाय कुछ और दिखाया गया हो। दूसरा, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाई गई हो।

जुलियन असांजेः हां, शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और मैं एक भी ऐसा केस नहीं जानता जिसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को गैर शारीरिक के अलावा भी कोई हानि पहुंचाई गई हो। अनेक राजनीतिज्ञों को त्यागपत्र देना पड़ा या राजदूतों को उन देशों को छोड़ना पड़ा जहां वे कार्यरत थे क्योंकि अपने प्रतिरुपों से वे जो झूठ बोलते रहे और वह उद्घाटित होने से उन देशों में उनका रहना असम्भव हो गया, सरकारें चुनाव हार गई हैं तथा मुबारक जैसे तानाशाहों को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन हम ऐसी किसी घटना के प्रति अनजान नहीं हैं – और न ही अमेरिका के किसी अधिकारी या किसी दूसरे ने यह आरोप लगाया कि – हमारे प्रकाशन से किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंची है।

एन. रामः तो न्याय ने जुलियन असांजे और विकीलीक्स को प्रेरणा दी है। यह आपका लक्ष्य है, आपके न्याय की अवधारणा?

जुलियन असांजेः हां, इसके पीछे एक तरीका और एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य न्याय है और विकीलीक्स तथा इसकी विभिन्न प्रकाशन गतिविधियों और सामग्री जुटाने की गतिविधियां वह तरीका है जिसका उपयोग हम करते हैं और एक अधिक न्यायसंगत समाज के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि आप पूछेंगे कि मैं इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा हूं, ठीक है अनेक ऐसे काम हैं जो मैं कर सकता हूं। मैं सौभाग्यशाली स्थिति में हूं जहां मैं अनेक चीजें कर सकता हूं और अनेक चीजें कर भी चुका हूं। लेकिन मैं देखता हूं कि यह दुनिया, मेरी दुनिया है और मैं अपनी दुनिया में अन्याय देखकर अप्रसन्न हूं। मैं समझता हूं कि यह दुनिया अपने में पूर्ण नहीं हैं और इसे देखकर मुझे दुरूख होता है। मैं खुश रहना चाहता हूं, इसलिए मैं दुनिया को और न्यायसंगत बनाना चाहता हूं।

***

जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वे जानते हैं कि विकीलीक्स एक निःशुल्क एनसाइक्लोपीडिया है। विकीलीक्स और इसके एडिटर–इन–चीफ जुलियन असांजे के बारे में ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, उनके लिए विकीपीडिया में उपलब्ध थोड़ी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

जुलियन असांजे (3 जुलाई, 1971) एक आस्ट्रेलियाई प्रकाशक और एक इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं। विकीलीक्स एक विसलब्लोअर (भण्डा फोड़ने वाली) वेबसाइट है। वेबसाइट के साथ जुड़ने से पहले वह भौतिकी और गणित के विद्यार्थी तथा कम्प्यूटर प्रोग्रामर रहे हैं।

असांजे अनेक देशों में रह चुके हैं और पत्रकारों को बता चुके हैं कि वह लगातार घूमते रहते हैं। वह समय–समय पर प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और खोजपरक रिपोर्टिंग के बारे में बोलने के लिए सामने आते हैं।

सन् 2009 में, असांजे ने 'केन्या में गैर–न्यायिक हत्याओं का पर्दाफाश करने' के लिए एमेनेस्टी इंटरनेशनल मीडिया

एवार्ड जीता। ब्रिटिश पत्रिका न्यू स्टेट्समैन ने उन्हें 2010 में दुनिया की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया।

घोटालेबाजों को सजा दो

भ्रष्टाचार को लेकर वास्तव में देश गुस्से में है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार इसलिए नहीं है कि आवश्यक कानूनों की कमी है, अपितु इसलिए है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनमें घोटालेबाजों को दण्डित करने की इच्छा शक्ति नहीं है।

इसलिए, संसद के मानसून सत्र में जब अण्णा हजारे द्वारा हासिल की गई कमेटी द्वारा इन दिनों विचारे जा रहे लोकपाल विधेयक पर विचार हो, भ्रष्टाचार से निपटने में सरकार की गंभीरता की असली कसौटी यह होगी कि पहले ही रहस्योद्घटित हो चुके तीन घोटालों – स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और मुंबई के भूमि घोटाले में यह क्या कार्रवाई करती है। जनता के लिए यह दूसरा कष्टप्रद तथ्य है कि पिछले वर्षों में अमेरिका और जर्मनी जैसे अधिक शक्तिशाली देश स्विट्जरलैण्ड जैसे टैक्स हेवन्स के बैंकिंग गुप्त कानूनों में सेंध लगाकर अपनी सम्पत्ति वापस लेने में सफल रहे हैं, जबकि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। इसने अभी तक सन् 2004 में पारित भ्रष्टाचार के विरूद्ध यू. एन. कन्वेंशन की पुष्टि तक नहीं की है।

भारतीयों द्वारा विदेशों में ले जाए गए अथाह काले धन को बिना किसी विलम्ब के वापस लाया जाए।

टेलपीस (पश्च लेख)

एन. राम के साथ एक घंटे के साक्षात्कार की समाप्ति पर जुलियन असांजे की अंतिम टिप्पणी काफी रोचक है। वह कहते हैं: "एक बात मैं दि हिन्दू और सामान्य रूप से भारतीय लोगों को कहना चाहूंगा। वह यह कि एक आस्ट्रेलियन होने के नाते, मैं आपको अंग्रेजीभाषियों से अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं।" ■

गांवों से निकलता है देश के विकास का रास्ता : नितिन गडकरी

मकराम मनोहर लोहिया सभागार में ग्राम्य सुराज संकल्प सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विकास का रास्ता गांवों की पगडंडियों से होकर जाता है। नाना जी देशमुख ने चित्रकूट में दिखा दिया है कि अगर गांवों की इस माडल के आधार पर होगी तो देश के साथ पार्टी का भी भला होगा। श्री गडकरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ करते हुए कहा मातृभूमि की सर्वांगीण उन्नति व विकास को लेकर उन्होंने काफी काम किया। विकास व सुशासन का नारा लेकर बिहार व गुजरात में भी यही प्रयोग किया गया। गुजरात में गरीब मेला लगता है जबकि मध्य प्रदेश में अन्त्योदय मेला लगता है। यह किसानों के हितों को साधकर किया जाने वाला काम है। गडकरी ने कहा कि भ्रष्टाचार को कम करके ही गरीब का विकास किया जा सकता है। कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद भगवान का काम मानकर करें। जिस दिन उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा तो दीन दयाल जी का सपना पूरा होगा। उन्होंने राजनीति के माध्यम से सामाजिक जीवन का गुर बताते हुये कहा कि कार्यकर्ता इसी तरह के उपाय अपनाकर ही देश में भाजपा का राज फिर से स्थापित करवायेंगे। अच्छा काम करेंगे तो लोग अपने आप प्रेमपूर्वक जुड़ेंगे। जातिवादी राजनीति का अंत भी अब अंतिम चरण में हैं। सत्ता का आधार राजनीति नहीं बल्कि समाज के लिए देश के लिए सभी को कार्य करना है। राज नहीं समाज बदलना है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को नसीहत देते हुये कहा कि अपने कार्य का रोजाना ही अवलोकन करें।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ग्राम स्वावलंबन व विकास के काम को और आगे ले जाने की जरूरत है। 'गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में' से खेतों व गांवों का भला होगा। खेती ऐसी हो जिससे किसान कमा सकें। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिये प्रयास करना होगा। इस दौरान कर्नाटक के पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री जगदीश शेट्टर, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री राम विचार नेताम, मध्य प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री मप्र गोपाल भार्गव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त गांधीवादी कमल टावरी भी मौजूद थे। ■

बाबा साहब अंबेडकर किसी व्यक्ति, पार्टी अथवा जाति के नहीं अपितु राष्ट्र के नायक है : प्रभात झा

Hkkरतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रभात झा ने अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक का समापन करते हुए महेश्वर में कहा कि मां नर्मदा के तट पर हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 35 विधानसभा सीटें जो अनूसूचित जाति

वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन सीटों पर विजय हासिल करेंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर काबिज है। लोकतंत्र में जीत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आने वाले महेश्वर के उपचुनाव में हम अवश्य जीत हासिल करेंगे। 2013 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा से आग्रह किया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अभियान मोर्चा को करना चाहिए, जिससे जनता पार्टी से जुड़े और भाजपा सरकार के विकास कार्यों को देखकर आने वाले विधानसभा चुनावों में हम पुनः सरकार बनाने में सफल हों। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य करें।

प्रभात झा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में हमें ऐसा जननेता मिला है, जो रात और दिन जनता की सेवा और मध्यप्रदेश के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर की 120 वी जयंती पर प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने शोषितों, पीड़ितों का सम्मान बढ़ाया और उन्हें संविधान सम्मत अधिकार दिलाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब किसी व्यक्ति अथवा जाति विशेष के नहीं, अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रेरणास्रोत है। प्रभात झा ने अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को बधाई देते हुए कहा कि मोर्चे ने सभी जिलों में कार्यकारिणी गठित कर व्यवस्थित कार्य किया है।

प्रभात झा ने कहा कि भाजपा सेवाभावी कार्यक्रम और हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर जन–जन तक पहुंचेंगी और समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली के लिए प्रत्यनशील होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव 2013 में विकास के दम पर तीसरी बार पार्टी की सरकार का शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठन होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 35 सीटों का काम के बल पर हकदार होगा। जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पिछड़ी है, वहां सघन प्रवास कर जनता का विश्वास जीतने के प्रयास होंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा इन क्षेत्रों का सघन प्रवास कर जन–जन से रू–ब–रू होंगे और विकास की गंगा बहायी जावेगी।

प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए प्रदेश भाजपा संगठनमंत्री श्री अरविन्द मेनन ने महेश्वर मे आयोजित दो दिवसीय भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी अहम भूमिका होती है। प्रत्येक कार्यकर्ता को शासन की कल्याणकारी योजनाओ को गरीब वर्ग के लोगों को बताकर उसका लाभ दिलाना चाहिए। हमारा लक्ष्य 10 से 15 प्रतिशत तक वोट बढ़ाना है।

इसके पूर्व कार्यसमिति का शुभारंभ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश के आजाद होने के समय कांग्रेस ने कहा था कि 10 वर्षो मे देश मे छुआछूत समाप्त कर दलितों का कल्याण करेंगे, परंतु कांग्रेस ने दलित वर्ग के वोट तो जरुर लिए किंतु उनका कल्याण नहीं किया। भाजपा ही ऐसा राजनैतिक दल है जिसने दलितों के सम्मान के लिए अनेक कार्य किए हैं।

शेष पृष्ठ 27 पर...

चीन की उल्लेखनीय प्रगति, परन्तु अतीत का अनादर नहीं

& jfo'kdj çlkn

पिछले दिनों एक संसदीय प्रतिनिधि के नेता के रूप में मैं चीन गया था। मेरे साथ राज्यसभा के सदस्य तरुण विजय और लोकसभा के सदस्य कांग्रेस के जी. विवेकानंद, हमदुल्ला सैयद तथा भाजपा के शिवकुमार उदासी गए थे। यह प्रतिनिधिमंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के निमंत्रण पर चीन गया था। भारतीय चौंबर्स ऑफ कामर्स के सांसद समन्वय सेल ने इसके संयोजन में सहयोग किया था। यह मेरी चीन की पहली यात्रा थी। हमारा दल चीन की राजधानी बीजिंग और दो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र शंघाई और सेंझन गया। यात्रा के दौरान शासन, कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स कांग्रेस के पदाधिकारियों, थिंक टैंक व शंघाई और सेंझन के म्युनिसिपल नेताओं से चर्चा करने के बाद एक बात स्पष्ट लगी–आज का चीन माओ त्से तुंग का चीन नहीं है, बल्कि देंग जियाओ पेंग का चीन है, जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। 60 से 70 के दशक में माओ के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी। उस समय दबाव में देंग जियाओ पेंग को हाशिए पर डाल दिया गया था, क्योंकि माओ के समर्थकों के अनुसार वे 'कैपिटलिस्ट रोडर' थे। माओ की मौत के बाद उन्होंने अपनी पूरी पकड़ बनाई और यह साफ घोषित किया कि हमें आर्थिक विकास करना है और इसके लिए पूंजी चाहिए जो कहीं से भी आ सकती है। हालांकि इसे भी साम्यवाद की विचारधारा के अनुरूप ही बताया गया।

सच्चाई यह है कि आज माओ और पारंपरिक कम्युनिस्ट विचारधारा, दोनों हाशिए पर हैं। चीन की मुद्रा पर माओ की तस्वीर जरूर छपी है। बीजिंग के थियेनमन चौक, जहां 1989 में हजारों लोकतांत्रिक समर्थक पुलिस और सेना की गोलियों से मारे गए, पर भी उनकी बहुत बड़ी तस्वीर टंगी है और वहीं उनका शव एक स्मृति स्थल पर संरक्षित रखा गया है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है, लेकिन पारंपरिक साम्यवाद सिद्धांत शासन में दिखाई नहीं पड़ता। माओ की चर्चा कम ही होती है। चीन का कोई भी बड़ा या छोटा नेता अब माओ का कोट नहीं पहनता, सभी सूट और टाई में ही मिलते हैं।

आज के चीन की कहानी 1978 के आर्थिक सुधारों से आरंभ होती है। चीन का आर्थिक विकास कई मामलों में प्रभावी और चौंकाने वाला भी है। सड़कें, बिजली, ढांचागत सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उद्योग एवं निर्माण, प्रमुख शहरों के विकास आदि में उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है। व्यापार की पूरी छूट है, परंतु कुछ परोक्ष नियंत्रण के साथ। शंघाई चीन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। वहां 60,000 विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं। इनमें भारत की कुछ कंपनियां भी हैं। चीन के संबंध दक्षिण कोरिया के साथ काफी तनाव भरे है, क्योंकि चीन उत्तर कोरिया का समर्थक है, फिर भी बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई कंपनियां वहां व्यापार करती है। यही हाल ताइवान की कंपनियों का भी है, जिस देश को चीन स्वीकार ही नहीं करता। सेंझन पिछले 25 वर्षों में बसाया गया बहुत ही सुंदर शहर है, जो विश्व का बहुत बड़ा फ्री इकोनोमिक जोन है। यहां आरंभ में 40,000 विदेशी कंपनियां थीं, जिनकी संख्या घट कर 20,000 रह गई है।

व्यापार और विदेशी मुद्रा के लिए चीन ने अपने पूरे दरवाजे खोल रखे हैं। चीन कंप्यूटर के हार्डवेयर में बहुत समृद्ध है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कमजोर है। चीनियों को इस बात का अहसास है इसीलिए आने वाले वर्षो में सॉफ्टवेयर के शोध पर अधिक ध्यान देने का निर्णय किया है। गांवों में तुलनात्मक रूप से विकास कम है। भविष्य की योजनाओं में चीन के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को शहरों में बदलने का प्रस्ताव है। लोकतांत्रिक क्रांतियों पर उनका कटाक्ष रहता है कि हमारे यहां जैसमीन क्रांति

हमने चीनी नेताओं से साफ–साफ कहा कि हम चीन से अच्छे रिश्तों के पक्षधर हैं, लेकिन जब तक सीमा विवाद, कश्मीर के संबंध में अलग से वीजा देने की नीति, अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानना तथा पाकिस्तान से भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद आदि विषयों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होता, तब तक रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे।

नहीं होती, सिर्फ जैसमीन चाय मिलती है।

चीन की राजनीति का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि साम्यवादी क्रांति होने के बावजूद उन्होंने अपने अतीत का अनादर कभी नहीं किया। राष्ट्रीयता का भाव और दुनिया की एक बड़ी ताकत होने का संकल्प उनके अंदर कूट–कूट कर भरा है। हजारों वर्षों तक चीन में विभिन्न राजवंशों ने राज किया है जिनमें हान, थंग, क्विंग आदि प्रमुख हैं। उनका योगदान विशेष रूप से चीन की राष्ट्रीय अस्मिता और चीनी भाषा की लिपि, जो पूरे देश में एक है–के निर्माण में उल्लेखनीय है। यह भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, जो भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा मात्र से नाक–भौं सिकोड़ने लगते हैं। शायद यही कारण है कि भारत के कम्युनिस्ट भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ सके और हाशिए पर चले गए। हमने चीनी नेताओं से साफ–साफ कहा कि हम चीन से अच्छे रिश्तों के पक्षधर हैं, लेकिन जब तक सीमा विवाद, कश्मीर के संबंध में अलग से वीजा देने की नीति, अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानना तथा पाकिस्तान से भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद आदि विषयों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होता, तब तक रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे। यह मानने के बावजूद भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकत हैं, जो दुनिया को प्रभावित करेंगी। वे इस आशंका से बुरी तरह घबराते भी हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत चीन के खिलाफ घेराबंदी करेगा।

संस्कृति और फिल्म के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की काफी गुंजाइश है। महात्मा बुद्ध, योग और कैलाश मानसरोवर इसके बड़े माध्यम हैं। आवारा फिल्म में राजकपूर के अभिनय की चर्चा अभी भी होती है। चीन रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा के उपनिदेशक ने अपना एक हिंदी नाम मीनाक्षी भी रख लिया है।■

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री है)

किरण माहेश्वरी बनीं भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 20 अप्रैल को श्रीमती किरण माहेश्वरी को राष्ट्रीय महामंत्री तथा श्रीमती सूरमा पाढ़ी एवं श्री श्याम जाजू को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। पार्टी की राष्ट्रीय सचिव रहीं माहेश्वरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुकी हैं। श्रीमती सूरमा पाढ़ी भी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उड़ीसा में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। जबकि श्री श्याम जाजू भाजपा मुख्यालय प्रभारी का भी दायित्व संभाल रहे हैं। ■

पृष्ठ 25 का शेष...

उन्होंने कहा कि तत्कालीन सुंदरलाल पटवा सरकार के समय प्रेरणा पुरुष डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थान महू के विकास के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए थे इसके पश्चात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 10 करोड़ की लागत से बाबा साहब जन्म स्थान को अम्बेडकर स्मारक बनाकर तीर्थ के रुप मे स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए आवंटित पैसे को भी कॉमनवेल्थ में खर्च कर दिया। केन्द्र की तत्कालीन गुजराल सरकार ने अनुसूचित जाति को दी जा रही अनेक सुविधाओं को बंद कर दिया था। अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन सुविधाओं को पुनः बहाल किया। भ्रष्टाचार व केन्द्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दलितों के हित में कार्य कर रही है।

कार्यक्रम का शुभारंभ माँ अहिल्या की धार्मिक नगरी के मध्य स्थित विक्रम कृष्णा खेल परिसर के हाल मे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 14 अप्रैल को प्रारंभ हुई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थावरचंद गहलोत का स्वागत मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष लालसिंह आर्य द्वारा किया गया। खरगोन जिला अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष राधेश्याम मण्डलोई द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुरज केरो ने किया। बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश प्रभारी नारायण केसरी, गौरीशंकर शेजवार, जगमोहन वर्मा, मंत्री जगदीश देवडा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेन्द्र यादव, प्रदेश मंत्री ज्योति यवतीकर सहित प्रदेश मोर्चा के समस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

समापन–सत्र को वरिष्ठ नेता नारायणसिंह केसरी ने भी संबोधित किया। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने बताया कि सभी 618 मंडलों में मोर्चा इकाई का गठन उपरांत सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। अनुसूचित जाति बहुल 35 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्राएं आयोजित की जावेगी जिनमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी भी भाग लेंगे। लालसिंह आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल गांवों को गोद लेकर विकास का ताना–बाना बुना जाएगा। ■

कांग्रेस और जनतंत्र

i- nhun;ky mik/;k;

एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता व भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्यायजी कुशल संगठक एवं विचारक राजनेता थे। समय–समय पर पत्र–पत्रिकाओं में लेख लिखकर कार्यकर्ताओं का वैचारिक मार्गदर्शन करते थे। हम यहां उनकी पुस्तक 'पॉलिटिकल डायरी' से 10 जुलाई 1961 को कांग्रेस पर लिखी एक टिप्पणी प्रकाशित कर रहे हैं, जो आज भी प्रासंगिक है।

गम लोगों ने संसदीय स्वरूप का जनतंत्र अपनाया है। संविधान के अंतर्गत दो आम चुनाव हो चुके हैं और तीसरा होने जा रहा है। किन्तु केवल संसद की स्थापना और क्या उसके निर्वाचित सदन होने का अर्थ संसदीय जनतंत्र की विद्यमानता नहीं है। ये केवल बाहरी रूप हैं, जो उस स्थिति में अपना सारा महत्व खो देते हैं यदि जनतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक आन्तरिक वृत्ति का उन लोगों में अभाव हो जो चुनाव में प्रत्याशियों के रूप में खड़े होते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हैं।यह सच है कि देश के मतदाताओं ने ,जिनकी संख्या विश्व में सबसे अधिक है,चुनावों में गहरी रूची दिखाई और उत्साह से भाग लिया। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हुआ। यह इस बात का द्योतक है कि जनता मूलतः जनतांत्रिक और शान्तिप्रेमी है।

किन्तु जनता से भी उन लोगों के विश्वास का, जो सत्तारूढ़ हैं या जो सत्ता हस्तगत करना चाहते हैं, अधिक महत्व है, जिसके द्वारा इस देश में जनतंत्र की प्रगति का मार्ग सरल होगा और वर्तमान संस्थान जनता की इच्छा को साकार रूप देने वाले प्रभावकारी साधन बन सकेंगे। हम यह मान लेने को उत्सुक हैं कि ऐसा विश्वास विद्यमान है। किन्तु हमारी कल्पना गलत भी हो सकती है,और अच्छा यह होगा कि राजनीतिक स्थिति पर समुचित रीति से विचार और उसका विश्लेषण किया जाए ताकि हम भान्ति में न पड़े रहें। हम अपने जनतांत्रिक अधिकारों को अक्षुण्ण और सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए।

स्वतंत्रता के आगमन और संविधान की घोषणा के बीच की अवधि को,जब देश के विभाजन से उत्पन्न समस्याओं सत्ता के हस्तांतरण और देशी राज्यों के भारत के साथ एकीकरण के कारण विशेष कार्यवाहियों की आवश्यकता थी,एक असाधारण कालावधि के रूप में छोड़ा जा सकता है, किन्तु उसके बाद सत्तारूढ़ दल ने जिस प्रकार आचरण किया है, उसकी समीक्षा आवश्यक है और तब यह दिखाई देता है कि उसने ऐसा कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया है जिससे जनतंत्र में विश्वास प्रकट होता हो। उल्टे घटनाएं विपरीत दिशा का ही संकेत देती हैं।

अब डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्तर के महान सांसदिक की नजरबंदी की स्थिति में रहस्यपूर्ण परिस्थियों में मृत्यु हो जाये ,और सारे प्रकरण की जांच न की जाय ,यह एक ऐसी ज्वलंत घटना है जिसने इस देश में संसदीय जनतंत्र के भविष्य के बारे में गंभीर शंका उत्पन्न कर दी। संसदीय पद्धति का अर्थ विचार –विमर्श के आधार पर चलनेवाली सरकार ,और उस पद्धति में अधिकारूढ़ व्यक्तियों को विरोधियों के दृष्टिकोण पर विचार करने तथा उसे मान्य करने के लिए सदा तैयार रहना होता है। इस पद्धति में अपने अटल विश्वास के साथ डा मुखर्जी ने प्रजा परिषद के सत्याग्रह से उत्पन्न प्रश्नों पर विचार –विमर्श हेतु प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बार–बार अनुरोध किया, परन्तु ने एक ऐसे व्यक्ति से मिलने और कश्मीर –प्रश्न पर विचार–विमर्श करने से इन्कार कर दिया जो वस्तुतः विरोधी दलों नेता था। किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को यह तर्क देकर शांत किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि संसदीय पद्धति बहुमत–दल केवल सरकार का गठन करता है। देश का शासन सरकार के माध्यम से संसद द्वारा किया जाता है।इस प्रकार विरोधी दल भी संसद द्वारा उत्तरदायित्वों के सफल निर्वाह में योगदान करता है, अन्यथा राष्ट्रद्रोह और विरोधी दल के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा

कहा जाता है कि एक बार जब पश्चिमी एशिया के एक अतिथि शाहंशाह

का ब्रिटिश पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता से परिचय कराया गया, और बताया गया कि उसे राजकोष से वेतन मिलता है ,तब अतिथि शासक उलझन में पड़ गया वह यह नहीं समझ पाया कि ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार का विरोध करता है,सरकारी कोष से वेतन दिया जाता है।' उसने कहा हम तो ऐसे व्यक्ति को गोली मार देना पसंद करेंगे 'किन्तु ,ब्रिटेन में 'हिज मैजेस्टी की सरकार ' के अतिरिक्त 'हिज मैजस्टी का विरोध –पक्ष भी है। सरकार विरोधी दल को केवल सहन ही नहीं करती, बल्कि उसका विश्वास भी करती है। भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल विरोधी पक्ष को तभी सहन कर सकता है, जब तक उसके अधिकार को हानि नहीं पहुंचती। वह विरोध पक्ष का विश्वास नहीं करता।

जनतंत्र में सत्ता के प्रति उच्च स्तर की निरासक्ति आवश्यक है। भगवान राम की भांति, जनतंत्र में राजनीतिज्ञ को, आह्वान मिलने पर सत्ता स्वीकार करने और क्षति की चिंता किए बिना उसका परित्याग कर देने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए। एक खिलाड़ी की भांति उसे विजय के लिए संघर्ष करना चाहिए ,किन्तु पराजय के लिए भी तैयार होना चाहिए। यदि वह पराजय को गौरव के साथ नहीं शिरोधार्य कर सकता, और अपने प्रतिस्पर्द्धी को उसकी विजय के लिए बधाई नहीं दे सकता, तो वह जनतंत्रवादी नहीं है। यही वह भावना थी जिसके साथ चर्चिल ने एटली को और एटली ने एडेन को सत्ता सौंपी दी। पर भारत में हमें क्या दिखाई देता है।

यहां वस्तुतः अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आयी है जब जनता के निर्णय के परिणामस्वरूप संपूर्ण सत्ता कांग्रेस के पास से किसी अन्य दल को हस्तांतरित की जाय। फिर भी ,कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल हटा दिए गए हैं और प्रतिष्ठा के उप चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा भी –अभिव्यक्त की गई प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं रही। इस प्रकार ,नयी दिल्ली लोकसभाई और कमला नगर नगर निगम उपचुनावों में

~~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

जनतंत्र में सत्ता के प्रति उच्च स्तर की निरासक्ति आवश्यक है। भगवान राम की भांति, जनतंत्र में राजनीतिज्ञ को, आह्वान मिलने पर सत्ता स्वीकार करने और क्षति की चिंता किए बिना उसका परित्याग कर देने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए। एक खिलाड़ी की भांति उसे विजय के लिए संघर्ष करना चाहिए ,किन्तु पराजय के लिए भी तैयार होना चाहिए। यदि वह पराजय को गौरव के साथ नहीं शिरोधार्य कर सकता, और अपने प्रतिस्पर्द्धी को उसकी विजय के लिए बधाई नहीं दे सकता, तो वह जनतंत्रवादी नहीं है।

~~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

कांग्रेसी प्रत्याशियों की पराजय के बाद उन लोगों ने जिस प्रकार आचरण किया ,वह इस बात को स्पष्ट करता है कि उन लोगों ने अपना संतुलन खो दिया और वास्तव में उनके मस्तिष्क की अजनतांत्रिक प्रवृत्तियों ने अपने–आपको बेपर्दा कर दिया है। कभी एक तर्क तो कभी दूसरे तर्क के आधार पर जनसंघ पर प्रतिबंध लगाने की जो चर्चा चल रही है, वह इस बात की द्योतक है कि जनतंत्र और मूलभूत अधिकारों के प्रति कांग्रेस –नेताओं का कितना आदर है? यह सच है कि इस प्रकार का प्रतिबंध संभव नहीं है,क्योंकि इससे कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जायेगी और इसलिए उसकी असफलता के अवसर भी घट जाएंगें,किन्तु उन लोगों के मन में ऐसे विचारों का उदय होना भी जनतंत्र में एक पाप है। सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने वाले जनरल अयूब और केवल अपनी रूचि के अनुकूल दलों को ही उनका अस्तित्व बनाये रहने देने वाले श्री जवाहर लाल नेहरू के बीच क्या अंतर है? जनतंत्र में यह पसंद जनता की होती है , शासनकर्ता की नहीं। यदि सत्तारूढ़ व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग करने लगे तो वह निरंकुश अधिनायकवाद की स्थिति होगी,जनतंत्र की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति तब तक जनतंत्रवादी होने का स्वांग कर सकता है ,जब तक उसे जनसमर्थन प्राप्त है, किन्तु जनतंत्रवादी बने रहने के लिए उस समय गहरी आस्था की आवश्यकता पड़ती है,जब आप हार जायें।

अपने वर्तमान रुख के कारण कांग्रेस जनतंत्र के लिए भारी संकट पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी, जिन्हें सदा एक जनतंत्रवादी समझा जाता रहा है, इस आरोप से नहीं बच सकते। वस्तुतः यह उनके भाषणों एंव उनके सोचने के ढंग का ही परिणाम है कि कांग्रेस अजनतांत्रिक दिशा में बढ़ रही है। यह आवश्यक है कि सभी जनतंत्रप्रेमी इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और भारत में किसी कैस्ट्रो के अभ्युदय के पहले ही निश्चयपूर्वक और प्रभावकारी पग उठायें।■

नहीं रहे सत्य साईं

nनिया भर में अपना आध्यात्मिक प्रभाव फैलाने वाले श्री सत्य साईं बाबा का देहांत लंबी बीमारी के कारण 85 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में हो गया। वे पिछले एक महीने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। मृत्यु की खबर फैलते ही देश–विदेश में फैले उनके भक्तजनों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साईं बाबा के महाप्रयाण की आधिकारिक घोषणा करते हुए श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट आफ हायर मेडिकल सांइस के निदेशक डा0 ए एन साफाया ने बयान जारी करते हुए कहा कि भगवान साईं भौतिक देह के साथ हमारे बीच नहीं रहे। हृदय और श्वसन प्रणाली फेल हो जाने के कारण बाबा ने 25 अप्रैल सोमवार 7:40 बजे देह त्यागी। उन्हें हृदय और सांस की तकलीफ के बाद 28 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

शोक संदेश

सत्य साईं महान सांस्कृतिक और सामाजिक हस्ती थे। उनका चले जाना एक शून्य पैदा करता है जिसे लंबे समय तक भरा नहीं जा सकेगा।

– नितिन गडकरी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी देश के लिए आदर्श और आध्यात्मिक जगत के नक्षत्र थे। ऐसे ही गुरू सत्य साईं बाबा का अनुयायियों पर प्रभाव था।

– लालकृष्ण आडवाणी,
अध्यक्ष भाजपा संसदीय दल

स्वामी सत्य सांई का सम्पूर्ण जीवन भारत ही नहीं विश्व में मानवता के कल्याण, शिक्षा का उत्थान, विश्व–शान्ति, सौहार्द और आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार को समर्पित था।

– राजनाथ सिंह
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

प्रेरक जीवनी : सत्य साईं बाबा

23 नवंबर 1926 को माता ईश्वरम्मा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा समाप्त की थी कि उन्हें प्रसव पीड़ा शुरु हुई और शिशु ने जन्म लिया। शिशु का नाम सत्यनारायण रखा गया। सत्यनारायण बचपन से ही गांव भर के लाडले थे। उनका सुंदर रूप, सहज मुस्कान और सरल प्रकृति सबको मोह लेती थी। बचपन से ही वे दयालु थे। और इसी दयालु प्रवृत्ति के कारण ही लोग उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहने लगे। और कहावत है न– कि 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात।' उन्होंने शिक्षा गांव की पाठशाला में ही ली। पढ़ने–लिखने में वे मेधावी थे। मात्र आठ वर्ष की आयु से ही वह ग्राम–नाटिका के लिए गीत लिखने लगे। पाठशाला के बाद हायर एलीमेंटरी स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन का घटनाचक्र आरंभ हुआ। कम ही समय में उनके करोड़ों अनुयायी बन गए और वर्तमान में भारत सहित विश्व के 165 देशों में उनके आश्रम स्थापित हैं।

सत्य साईं का जीवन प्रेरणादायी था। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जो भी एक बार मिल लेता था, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च कोटि के विभूति तो थे ही इसके साथ–साथ उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। गरीबों को मुफ्त शिक्षा के लिए कई विद्यालय खुलवाए तो चिकित्सा सुविधा के लिए सुविधासंपन्न अस्पताल बनवाए।

इस तरह वह एक समाज सेवक के रूप में हमारे सामने आए और 24 अप्रैल 2011 को वह इस भौतिक संसार को अलविदा कह गये। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। वे दयालु थे और उनका धर्मं एकमात्र था–मानवता। और सारा जीवन उनका मानवता को समर्पित था। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~